बातों बातों में
आपका सरोकार

राष्ट्रीय हिंदी मासिक समाचार पत्र

बातों बातों में

संपादक पुष्पा रानी

- स्वामी विवेकानंद

उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाये।

••••

खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है।

••••

एक रास्ता खोजो। उस पर विचार करो। विचार को जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो। सपना देखो, जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो। सफलता का यही रास्ता है।

••••

शुक्रवार 5 फरवरी 2021 | वर्ष: 01 | अंक: 03 | पृष्ठ: 08 | वार्षिक मूल्य: 500/- | Title Code : HARHIN11298 | Email: batonbatonmeinnews@gmail.com

अंतोदय व सामाजिक समरसता हमारी सरकार का मूल मंत्र है: मनोहर लाल

रणदीप रोड़/बातों बातों में

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अंतोदय व सामाजिक समरसता हमारी सरकार का मूल मंत्र है और महर्षि वाल्मीकि जी की कल्पना भी राम राज्य है जिसको चरितार्थ करने के लिए देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें महर्षि बाल्मीकि जी की कल्पना के अनुरूप विकास के पथ पर अग्रसर हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बात गत दिवस देर सायं अपने निवास पर आए वाल्मीकि एवं मजहबी सिख समाज के एक शिष्टमंडल से भेंट वार्ता के दौरान कही। इस शिष्टमंडल की अगुवाई मुख्यमंत्री के राजनैतिक सचिव कृष्ण बेदी द्वारा की गई जबकि अध्यक्षता पंजाब के पूर्व विधायक सरदार इंद्र इकबाल सिंह अटवाल ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाएं देश को विश्व शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। उन्होंने वाल्मीकी एवं मजहबी सिख समाज से हरियाणा के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक मसलों पर चर्चा भी की। इस भेंट वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तक ''वाल्मीकिप्रशस्तिकाव्यम'' का विमोचन भी किया।

अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रकाशित यह दूसरी पुस्तक है जो वाल्मीकी जी के जीवन दर्शन के बारे में आमजन को जानकारी देगी। वाल्मीकी जी ने रामायण और योगवाशिष्ठ जैसे आदर्श काव्य दिये हैं, जिन्हें साहित्य, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों का रतनाकर कहा जा सकता है। महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर पुस्तकों के अभाव की पूर्ति के लिए महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद् कई वर्षों से कार्यरत है। इस अवसर पर शिष्टमंडल द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री को शॉल व सरोपा भेंट करके सम्मानित भी किया गया। इस शिष्टमंडल में संत मनशाह जी महाराज, सेवा निवृतन्यायाधीश, पूर्व विधायक, हरियाणा सरकार में रहे प्रतिनिधि, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रमुख लोग शामिल थे। शिष्टमंडल में संत मनशाह जी महाराज के अलावा मुख्यरूप से विश्व हिंदू परिषद् के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन कुमार, सेवानिवृत न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार, प्रकाश तंवर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा के पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका, फूल सिंह खेड़ी, सुमन बेदी मौजूद रहे।

नागरिक विमानन क्षेत्र में हरियाणा निभाएगा अहम भूमिका :दुष्यन्त

पुष्पा रानी/बातों बातों में

चंडीगढ़:हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि नागरिक विमानन क्षेत्र में हरियाणा अपनी अहम भूमिका निभाएगा। जल्द ही प्रदेश में विमानों की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए तीन हैंगरों का निर्माण पूरा हो जाएगा।

वे आज बेंगलुरु में 'एरो इंडिया–2021' के उदघाटन अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लेने गए हुए हैं। डिप्टी सीएम, जिनके पास नागरिक एवं विमानन विभाग का प्रभार भी है, ने कहा कि हरियाणा सरकार की दूरगामी एवं आशावादी सोच के कारण राज्य में नागरिक विमानन क्षेत्र में क्रांति आई है। उन्होंने बताया कि सरकार एक अहम परियोजना लेकर आई है। इसके तहत प्रथम चरण में हवाई अड्डा हिसार को प्रथम लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा करवाना था जिसका गौरव हवाई अड्डा हिसार को सितंबर 2018 में प्राप्त हुआ। साथ हीसाथ श्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण योजना RC के तहत छोटे विमानों से आमजन का क्षेत्रीय गंतव्यों के लिए आवागमन प्रारंभ करना था। इसी क्रम में भारत में पहली बार छोटे विमानों (एयर टैक्सी) द्वारा उड़ान परियोजना के तहत हवाई यात्रियों का विभिन्न गंतव्यों के लिए आवागमन शुरू किया गया तथा यह सुचारू रूप से चल रहा है। द्वितीय चरण में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं दस हजार फीट लंबे रनवे का निर्माण शामिल है।

इसके तहत प्रथम चरण में हवाई अड्डा हिसार को प्रथम लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा करवाना था जिसका गौरव हवाई अड्डा हिसार को सितंबर 2018 में प्राप्त हुआ। साथ ही साथ श्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण योजना RC के तहत छोटे विमानों से आमजन का क्षेत्रीय गंतव्यों के लिए आवागमन प्रारंभ करना था। इसी क्रम में भारत में पहली बार छोटे विमानों (एयर टैक्सी) द्वारा उड़ान परियोजना के तहत हवाई यात्रियों का विभिन्न गंतव्यों के लिए आवागमन शुरू किया गया तथा यहसुचारू रूप से चल रहा है। द्वितीय चरण में पर्यावरणीय स्वीकृति एवं दस हजार फीट लंबे रनवे का निर्माण शामिल है। इंटेग्रेटेड एविएशन हब बनाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है एवं रनवेबनाने का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ हो चुका है। साथ ही विमानों की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए तीन विशाल हैंगरो का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है जिसमें एयरबस 320, बोइंग, ए.टी.आर, Q–400 इत्यादि विमानों का सुविधा पूर्वक रख–रखाव किया जा सकता है। तीसरे चरण में दो समानांतर रनवे, विशाल टर्मिनल बिल्डिंग एवं कार्गो पोर्ट इत्यादि का निर्माण कार्य शामिल है।

श्री चौटाला ने कहा कि इस परियोजना से हवाई प्रशिक्षण, हवाई संचालन एवं मरम्मत इत्यादि के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं सम्मिलित हैं ।

कृषि कानून वापिस लेने की मांग पर हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने किया राजभवन तक पैदल मार्च

बातों बातों में

चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में गुरुवार को कांग्रेस विधायकों ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। मार्च को राजभवन के पास पुलिस ने बैरीकेटिंग करके रोक दिया।

बारिश के बीच कांग्रेस विधायक राजभवन के पास बैरीकेटिंग पर खड़े रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि वो लगातार राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त देने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि प्रजातंत्र में सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का अपना–अपना महत्व है। जनता की आवाज राज्यपाल तक पहुंचाना प्रतिपक्ष का संवैधानिक अधिकार और प्रतिपक्ष की बात सुनना राज्यपाल का कर्तव्य है। लेकिन प्रतिपक्ष को मिलने का समय ना देकर राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलने की मांग कर रही है। ताकि प्रदेश के मौजूदा हालात और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जा सके। इस सत्र में कांग्रेस एपीएमसी एक्ट में एमएसपी गारंटी का संशोधन और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी।

क्योंकि बीजेपी–जेजेपी गठबंधन सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जनविरोध के चलते मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकार समर्थित विधायक अपने चुनाव क्षेत्रों में जाने से भी बच रहे हैं। इस बीच सत्ता समर्थित कुछ विधायक जनता के बीच में सरकार के विरोध की बात करते हैं लेकिन चडीगढ़ आकर उसी सरकार को समर्थन देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से साफ हो जाएगा कि कौन–सा विधायक जनता के साथ है और कौन–सा सरकार के साथ। सरकार इस अविश्वास प्रस्ताव से इसलिए डरी हुई है क्योंकि अगर विधानसभा में ये प्रस्ताव आता है तो जनता सत्ताधारी विधायकों पर जनविरोधी सरकार के खिलाफ वोट देने का दबाव बनाएगी। क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिरती है तो इससे केंद्र सरकार पर दबावबनेगा और वो किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापिस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। इसी डर से ही विधानसभा स्पीकर ने कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को बिना कोई नोटिस या वक्त दिए उनकी सदस्यता रद कर दी।

हुड्डा ने कहा कि इस्तीफा ना देकर अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के खिलाफ मतदान करना चाहिए, वो इस्तीफा देकर मतदान से बच रहे हैं और जिन्हें जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से इस्तीफा देना चाहिए था, वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। अभय चौटाला के इस्तीफे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि साल 2000 में जब इनेलो सरकार के दौरान कंडेला में किसानों को गोलियों से भूना जा रहा था, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव से उन लोगों का सच सबके सामने आ जाएगा जो किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रहे हैं और सरकार के साथ अप्रत्यक्ष गठबंधन चला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐलनाबाद और कालका की सीट खाली होने से सरकार को कुछ राहत जरूर मिली होगी। लेकिन ये निश्चित है कि जनता का विश्वास खो चुकी ।लेकिन इस तरह सरकार अपने बोझ से खुद ही गिर जाया करती है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शराब घोटालों के लिए इस्तीफा दें–सुरजेवाला

बातों बातों में

चंडीगढ़:वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोरोना काल में अरबों रुपए के शराब घोटालों और पचास से ज्यादा लोगों की मौतों के लिए उपमुख्यमंत्री और एक्साइज मंत्री दुष्यंत चौटाला से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की है।

सुरजेवाला ने कहा कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जाँच से ही हरियाणा शराब घोटालों के असली किंगपिन और गुनहगार पकड़ में आएंगे। राज्य सरकार को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले और पचास जिंदगियां लीलने वाले शराब घोटालों में एसआईटी की जांच सच को सामने लाने में अक्षम है। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्या इतना बड़ा घोटाला बिना राजनीतिक और चंडीगढ़ के सचिवालय के संरक्षण के संभव हो सकता है? अहम सवाल यह है कि क्या वे विभागीय अधिकारी बिना किसी राजनीतिक शह या बड़ी ताकत के आदेश के इतना बड़ा घोटाला कर सकते थे ? क्या विभाग के मंत्री और उपमुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?

क्या उन्हें बिना जांच और पूछताछ के क्लीन चिट दी जा सकती है? क्या हरियाणा की कोई एजेंसी उनके पदों पर रहते निष्पक्ष जांच कर सकती है? शराब घोटाले की आधी–अधूरी 'जाँच' में छोटी मछलियों पर सारा दोष डाल राजनीतिक रसूख वाले असली गुनाहगारों का कौन बचाव कर रहा है? मुख्यमंत्री खट्टर से सीधा सवाल करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि इतने बड़े घोटालों के बावजूद बड़ी मछलियों से कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई। अगर पूछताछ ही नहीं होगी तो कार्यवाही कैसे संभव है, इसलिए हमें एसआईटी की जांच से सच बाहर आने कोई उम्मीद नहीं है।

शेष पृष्ट 2 पर

भाजपा के लिए परेशानी पैदा कर सकता है पूरे देश में फैलता जा रहा किसान आंदोलन

रणदीप रोड़
नई दिल्ली/ बातों बातों में

लगभग 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली के मुहाने पर बैठे किसानों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। 26 जनवरी के बाद एक बार टूटने के कगार पर पहुँच चुके इस आंदोलन में राकेश टिकैत के आंसुओं ने जो जोश भरा वह अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है।

पंजाब व हरियाणा से शुरू हुआ ये आंदोलन अब पश्चिमी उत्तरप्रदेश के रास्ते पूरे भारत में फैलता जा रहा है। दक्षिण भारत से भी हजारों किसान दिल्ली पहुँच चुके हैं। उत्तरप्रदेश व हरियाणा से शुरू हुई किसान महापंचायतें भाजपा के लिए परेशानी पैदा करने वाली हो सकती हैं। यह वही क्षेत्र हैं जहां भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। इन क्षेत्रों के किसानों का छिटकना भाजपा के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि अगले साल उत्तरप्रदेश व पंजाब जैसे बड़े प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।

सरकार को हल्के में लेना पड़ गया भारी

सितंबर 2020 में जब संसद ने तीन नए कृषि कानून पास किए तब किसानों का विरोध–प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा में ही नजर आ रहा था।

केंद्र सरकार यही समझती रही कि पंजाब व हरियाणा के चावल और गेहूं उत्पादक किसान ही नाराज हैं लेकिन जैसे ही इन किसानों ने दिल्ली कूच किया और दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला तो आंदोलन व्यापक हो चला। फिर उत्तरप्रदेश से भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में भी किसान यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर आन डटे। 26 जनवरी के बाद तो परिस्थितियों के ऐसी करवट बदली कि टूटने के कगार पहुँच चुके इस नाडोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर से बादल कर गाजीपुर नजर आने लगा। इसके बाद तो राजनीतिक पार्टियों की सीधे तौर पर इसमें समर्थन देना शुरू कर दिया। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी, किसानों में विशेष पकड़ रखने वाली राष्ट्रीय लोक दल, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस और भीम आर्मी के चंद्रशेखर समेत कई ने इसे अपना समर्थन दिया। अब यह आंदोलन पंजाब, हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंच चुका है।

किसानों से मिलने जा रहे 15 सांसदों को रोका

नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से गुरुवार को मुलाकात करने के लिए जा रहे दस विपक्षी दलों के 15 सांसदों को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर जाने से रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व गठबंधन सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए सरकार पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट कर आश्चर्य जताया कि सांसदों तक को किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

ये प्रदेश भी हो सकते हैं प्रभावित

किसान आंदोलन का प्रभाव पूरे देश में भी पड़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। 2022 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होने हैं, और वहां भी भाजपा सत्ता में है। उससे पहले इसी साल अप्रैल–मई में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होंगे, जहां वामदलों के साथ–साथ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस भी भाजपा को किसान विरोधी ठहराने में जुटी है। वामदलों ने इसके लिए खास तैयारियां की हैं और महिला किसानों के मोर्चे उतार दिए हैं।

अनीता कुमारी को मिली माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी की डिग्री

पुष्पा रानी
कसौली (हिमाचल प्रदेश)/बातों बातों में

केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिमाचल प्रदेश में सहायक प्रावैधिक अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए कोरॉना समय में अपनी उच्चतम शिक्षा पर भी ध्यान दिया। इसलिए नारी शक्ति महान है जो अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य को भी प्राप्त करती है।ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान में है,जो कि भारत में राज्य स्तर पर निजी प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अनीता कुमारी को एकाग्रता और कड़ी मेहनत से अपने अनुसंधान कार्य को पूरा करने के बाद ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर राजस्थान द्वारा माइक्रो बायोलॉजी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी की डिग्री प्रदान की गई। उनके पति डॉ. सुरेश मिश्रा जो कि ज्योतिष, अंक शास्त्र, हीलिंग और वास्तु अनुसंधान द्वारा जनमानस को सम्पूर्ण विश्व में अपनी विशेष सेवाएं प्रदान कर रहे है । वह कॉस्मिक एस्ट्रो ओपीसी प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और श्री दुर्गा देवी मन्दिर, पिपली, कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष भी है।

गोबरधन योजना को बढ़ावा देने और प्रगति की निगरानी के लिए एकीकृत पोर्टल लॉन्च

नई दिल्ली/ बातों बातों में

केंद्रीय मंत्रियों ने संयुक्त रूप से गोबरधन एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया।

इस एकीकृत पोर्टल के तहत प्रमुख हित धारकों में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई) और ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न बायोगैस कार्यक्रम/ नीतियां/योजनाएं जैसे कि एमएनआरई कानया राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनएनबीओएमपी), एमओपीएनजी की जैवईंधन नीति और किफायती परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प (सतत) और पशुपालन विभाग की ओर से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और इसी प्रकार की अन्य योजनाएं शामिल हैं। नवीन एकीकृत दृष्टिकोण के तहत इन सभी कार्यक्रमों/योजनाओं का समन्वय पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण (एसबीएमजी) के अधीन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने उद्घाटन भाषण ने कहा कि एसबीएमजी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में खुद को स्वच्छता के लिए आंदोलन में बदला और ग्रामीण भारत में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) का लक्ष्य मिशन मोड में हासिल किया है। इस असाधारण सफलता को आगे ले जाते हुए, एसबीएम (जी) का दूसरा चरण पिछले साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था जिसका फोकस गांवों में समावेशी स्वच्छता प्राप्त करने या ओडीएफ प्लस स्टेटस को बनाए रखने के लिए खुले में शौच की संवहनीयता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) करना है। उन्होंने आगे कहा कि ओडीएफ प्लस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोबरधन योजना को 2018 की शुरुआत में लॉन्च किया गया थाजिसका उद्देश्य गावों में मवेशियों के अपशिष्ट समेतअन्य जैव–अपशिष्ट का प्रबंधन करना और उन्हें बायोगैस तथा ऑर्गेनिक खाद में बदलना है ताकि किसानों और अन्य घरों को आर्थिक और संसाधनों के लाभ पहुंचाकर उनके जीवन में सुधार किया जा सके। उन्होंने इस नई एकीकृत दृष्टिकोण रणनीति की प्रशंसा की और कहा कि एकीकृत गोबरधन पोर्टल बायोगैस योजनाओंध्पहलों के सुचारु कार्यान्वन और वास्तविक समय में इसकी निगरानी करने के लिए सभी हितधारक विभागों/मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में गोबरधन के 'अपशिष्ट से संपत्ति' पहलू की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत बड़ी मात्रा में जैव–अपशिष्ट का उत्पादन करता है जिसका कुशलता पूर्वक उपयोग करके बेहतर जन स्वास्थ्य और पर्यावरण कालक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह जैव–अपशिष्ट प्रोसेसिंग से जुड़ी उचित पहलों और योजनाओं के जरिए किया जा सकता है, विशेषकर मवेशियों के गोबर को बायोगैस और ऑर्गेनिक खाद में बदलकर रोजगार और घरेलू बचत के अवसरों का सृजन किया जा सकता है।उन्होंने अपने विभाग के अधीन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही सहकारी योजनाओं के सफल मॉडल का उल्लेख किया जिनमें गौशाला और दुग्ध सहकारी समीतियों को बड़े समुदाय आधारित बायोगैस इकाइयों से जोड़ा जा रहा है।उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वास जताया कि गोबरधन एकीकृत पोर्टल विभिन्न बायोगैस परियोजनाओं/ मॉडलों और पहलों के लिए सम्मिलित दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। एसबीएमजी के दूसरे चरण में रेखांकित किए गएओडीएफ प्लस उद्देश्य काफी हद तकगोबरधन योजना के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं क्योंकि इसमें ना केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जाएगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों मेंजीविकोपार्जन की संभावनाओं और घरेलू आय में भी बढ़ोतरी करेगा। इस एकीकृत पोर्टल के लिए लिंक http://sbm-gov-in/gbdw20 है।

इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया उपस्थित रहे।

राहुल गाँधी किसानो के कंधो पर बंदूक रखकर सेक रहे है अपनी राजनितिक रोटियां: कटारिया

कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

केन्द्रीय जलशक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किसान आंदोलन को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीटस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में कुछ निहित स्वार्थी समूहों ने भारत के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास किया है। उन्होंने किसान आंदोलन के विषय को देश का आंतरिक मुद्दा बताते हुए इस विषय पर सरकार के विरूद्ध प्रतिक्रिया देने वाली अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को सुझाव दिया कि वे बयानबाजी करने से पहले इस मुद्दे की गंभीरता को समझें। ऐसे लोगों को बिलों की सही जानकारी नहीं है तथा वह भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी ऐसे बयानों पर आपत्ति जाहिर करते हुए देश के आंतरिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप न करने के लिए आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त देश की खेल, कला तथा सिनेमा जगत की कुछ प्रमुख हस्तियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों की प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी के उपद्रवियों को रिहा करने के बयान पर श्री कटारिया ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वे सडकों पर दोबारा लड़ाई कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन सडकों पर उपद्रव हुआ तब राहुल गाँधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा था कि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जब उपद्रवियों पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है तब वे उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सरकार ने किसानों को बार–बार बातचीत करने का न्यौता दिया है और सरकार इस विषय पर खुले मन से किसानों से बिंदूवार बात करने को तैयार है।

बजट विश्लेषण 2021- 22: आजादी के बाद बीमार चल रहे हेल्थ सेक्टर पर 137 फीसदी बढ़ाया बजट

डॉ ह्वा सिंह पूर्व रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

कोरोना बीमारी के बाद किए गए लॉकडाउन से परास्त अर्थव्यवस्था के बीच केंद्र सरकार ने 2020 –2021 का बजट पेश किया।

इस बजट का कुल खर्चा 3483238 करोड़ है। रिवेन्यू खर्चा 29 लाख 29 हजार करोड़ है, जो सैलरी, पेंशन व लोन की वापसी पर खर्च होगा। कैपिटल खर्चा 554236 करोड़ रुपए विकास के कार्यों में खर्च होगा। बजट में आय की राशि 1976424 करोड़ रुपेए होगी जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, आयकर, कारपोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होगी व 1.75 लाख करोड रुपए विनिवेश से हासिल की जाएगी। लगभग बाकी राशि 9 67708 करोड सरकार बाजार से कर्ज लेगी तथा 400000 करोड रुपए छोटे बचत पर जारी किए गए सिक्योरिटीज से जुटाएगी। अगले वित्त वर्ष में 6.8 परसेंट फिसकल घाटे का लक्ष्य रखा गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट10 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। 13 सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम को लाया जाएगा। अगले 3 साल में देश भर में 7 टैक्सटाइल पार्क बनाए जाने की योजना है। नेशनल

इन्फ्राट्रक्चर पाइप लाइन के जरिए 7400 प्रोजेक्ट लाए जाएंग।

स्वास्थ्य सेक्टर

आजादी के बाद बीमार चल रहे हेल्थ सेक्टर पर 2.23 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। यह लगभग 137 फीसदी बढ़ाया गया हैस कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से 35000 करोड रुपए फंड का इंतजाम किया गया है। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च होगास 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। 64180 करोड़ की राशि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना भी इस में शामिल है। इस योजना के तहत 70000 गांव में वैलनेस सेंटर बनाए जाएंगे।

बजट काफी हद तक सकारात्मक है

राजनैतिक दलों, किसान संगठनों, व्यापारियों तथा अर्थशास्त्रियों ने इस बजट की आलोचना की है। इनका मानना है कि वित्तीय तथा राजकोषीय घाटा लगभग 9 से 10 फीसदी तक पहुंच जाएगा और एफआरबीएम एक्ट 2003 की फिस्कल डेफिसिट दर का उल्लंघन हुआ है क्योंकि इस एक्ट के तहत यह दर 3% तक होनी चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यह बजट निजीकरण व प्राइवेट निवेश की ओर देश की अर्थव्यवस्था को ले जा रहा है क्योंकि इस बजट में दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचने तथाकई सरकारी कंपनियों को भी विनिवेश करने का प्रावधान किया गया है। उनको ऐसा लगता है कि सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को आर्थिक सत्ता सौंपने की मनसा रखती है । रक्षा बजट में भी मामूली वृद्धि की गई है जबकि भारत के पुराने प्रतिद्वंदी चीन व पाकिस्तान से सीमा पर खतरे व चुनौतियां बरकरार हैं। आयकर छूट सीमा बढ़ाकर ₹500000 की जाती तो इसे बाजार की लिक्विडिटी बढ़ती। इंप्लाइज संगठनों का मानना है कि पहले ही सरकार ने कोविड–19 की वजह से उनका महंगाई भत्ता पहले ही बंद कर दिया था तथा उनके ऊपर इनकम टैक्स का और बोज डाल दिया है क्योंकि सेवानिवृत्त कोस पर कर मुक्त ब्याज की सीमा को वार्षिक 2.5 लाख रुपए तक सीमित कर दिया है। किसान संगठन ने भी इस बजट का विरोध किया है उनका मानना है कि इस बजट में खेती कर्जा राशि बढ़ा दी गई है जिससे किसान और कर्जदार होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस बजट में जिक्र नहीं किया गया है । इस बजट में मध्यमवर्ग ,महिलाओं व नौजवान बेरोजगारों के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। अ सी, एसटी व महिलाओं को स्टैंड अप इंडिया के तहत मार्जिन मनी दी जाती थी , इस को 25% से 15% कर दिया गया है। पेट्रोलियम सब्सिडी को भी पिछले वर्ष की अपेक्षा 64% कम कर दिया गया है। ग्रामीण विकास योजना के तहत 2 करोड 23 लाख मकान बनने थे लेकिन अब तक एक करोड़ 27 लाख मकान ही बन पाए। वर्तमान परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह बजट काफी हद तक सकारात्मक दिखाई देता है,इसके अतिरिक्त इस बजट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार कितनी दृढ़ इच्छा व पारदर्शिता से इसको कार्यान्वयन करने में सफल होती है। यह भविष्य के गर्भ में है।

कृषि क्षेत्र

कृषि क्षेत्र को इस बजट में काफी प्रोत्साहन दिया गया है। खेती के विकास के लिए 131531.19 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 8362. 58 करोड रुपए खेती में शोध के लिए रखा गया है। 2021–22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जल्द खराब होने वाली 22 फसलें भी शामिल की जाएगी। कोचीन, चेन्नई, विशाखा पट्टनम, प्रायद्वीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्वर बनेंगे। मंडियों को आधुनिक सुविधाएं तथा कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बजट में ऐलान किया है कि पेट्रोल पर 2.50 प्रति लीटर तथा डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का एग्रीकल्चर इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा। इससे आम उपभोक्ता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान योजना का बजट 75000 करोड़ से कम करके अब 65 हजार करोड़ कर दिया है। खाद पर 79530 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। लोन,खेती के उपकरणों तथा गेहूं व धान के अलावा दूसरी फसलों के प्क्योरमेंट पर 33460 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा।

इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई

बजट में इनकम टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। भविष्य निधि कोष पर कर मुक्त ब्याज की सीमा को वार्षिक 2.5 लाख तक सीमित कर दिया गया हैस हालांकि अवकाश यात्रा रियायत पर कर छूट देने की घोषणा हैस अब बजट में कोटन, सिल्क, लेदर, मोबाइल, जवाहरात, एलइडी बल्ब, शराब तथा फ्रिज/एसी महंगे होंगेस नायलॉन कपड़े, लोहा, स्टील, कॉपर सोना व चांदी और प्लैटिनम सस्ते होंगेस नायलॉन कपड़े ,लोहा ,स्टील ,कॉपर सोना व चांदी और प्लैटिनम सस्ते होंगे । कोविड–19 महामारी और राजस्व में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया । सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने एवं देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने का कार्य किया है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा की ओर ले जाएगा। इससे हेल्थ व कृषि सेक्टर की सूरत बदलेगी। स्वस्थ राष्ट्र से धनी और रचनात्मक राष्ट्र बनाने का रास्ता प्रशस्त होगा। ऑपरेशन ग्रीन इरिगेशन फंड व प्रधानमंत्री बीमा योजना, कृषि कार्ड की सुविधाओ से किसानों की आय 2022 तक दुगनी आय का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की घोषणा की है जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अल्पसंख्यक ,महिलाएं,बच्चे व अनुसूचित जातियों के विकास का स्पेशल ध्यान रखा गया है। हेल्थ केयर सेक्टर पर ज्यादा बजट से नई बीमारियों की रिसर्च में भी काम होगा। आर्थिक सुधारों से लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बैंकों की वित्तीय प्रबंध को दुरुस्त करने के लिए कई कदम सुझाए गए हैं जैसे बैड बैंक की स्थापना इत्यादि। शेयर बाजार की तेजी से सकारात्मक संदेश मिलता है।

जल जीवन

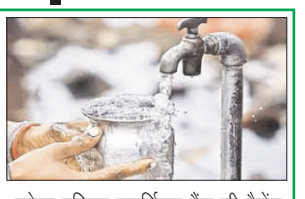

शहरी जल जीवन के लिए 2.87 लाख करोड़ रखे गए हैं। इस मिशन का मकसद सभी 4378 शहरी निकायों के घर–घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाना है। 2.86 लाख घरों में नल लगेंगेस कचरा प्रबंधन के लिए 1.78 लाख करोड़ दिए हैं।10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2.2 17 करोड़ दिए हैं। फूड व पब्लिक वितरण व उपभोक्ता वेलफेयर के बजट में 48 परसेंट की वृद्धि की गई है। फूड सब्सिडी के लिए 2.42 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया हैस फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के पेंडिंग ड्यूज को क्लियर करने के लिए 1.15 लाख का भी प्रयोजन किया गया है मनरेगा के लिए 73000 करोड़ का प्रयोजन किया गया है। बच्चों व महिलाओं की भलाई के लिए 239039 करोड़ खर्च करने का अनुमान है। इंश्योरेंस में 74 परसेंट विदेशी निवेश की इजाजत दे दी गई है।इंफ्रास्ट्रक्चर को वित्तीय सहायता उपलब्धि के लिए डिवेलपमेंट फाइनैंशल संस्था का निर्माण किया जाएगा। इस बजट में एक बेड बैंक बनाने का भी प्रपोजल दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पब्लिक कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट को साफ सुथरा करना है तथा जो बैंकों का एनपीए है उसको इस बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि इसमें से पेंशन का भुगतान हटा दिया जाए तो रक्षा क्षेत्र का बजट 3.62 लाख रह जाएगास विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बजट में 14793. 6 6 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चार राज्यों में 69 75 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़क का निर्माण पर 1.19700 लाख करोड़ पर खर्च किए जाएंगे। शहरी इलाकों में 20000 नई बसें चलाई जाएंगी। रेलवे को 1.10 लाख करोड़ दिए हैं, इसमें 1.07 लाख करोड़ नए प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं। दिसंबर 2023 तक रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा।नए वाहन कबाड़ नीति के मुताबिक 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों को सेक्रेप किया जाएगा, जबकि निजी वाहन की अवधि 20 वर्ष तक की गई है।

शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र देश की तरक्की के लिए अहम रोल अदा करता है। शिक्षा का बजट 85089 करोड़ से बढ़ाकर 93224 करोड़ रूपया किया है, जो कुल बजट का 2% है। उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा। 15000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा।

100 से ज्यादा सैनिक स्कूल पब्लिक प्राइवेट साझेदारी में खोले जाएंगे। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। 38 करोड़ की लागत से आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के लिए एक करोड़ आवंटित किया जाएगा।

फ्रंटलाइन कोरोना योद्वाओं को वैक्सीन डोज, डी जी पी मनोज यादव ने लगवाया पहला टीका

पंचकूला/बातों बातों में

हरियाणा पुलिस के फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं के लिए कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को पुलिस मुख्यालय पंचकूला से हुई। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने पहल करते हुए पहला टीका लगवाया। कोविड महामारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए टीका लगवाने वाले अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। अभियान के पहले दिन सबसे पहले डीजीपी ने टीका लगवाकर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को हौसला बढ़ाया। इसके बाद डीजीपी राज्य सतर्कता ब्यूरो पीके अग्रवाल, डीजीपी क्राइम मोहम्मद अकील, एडीजीपी प्रशासन और आईटी एएस चावला, एडीजीपी सतर्कता अजय सिंघल, आईजीपी डॉ. एम रवि किरण, आईजीपी राजिंदर कुमार, सीपी पंचकूला सौरभ सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने टीका लगवाया। डीजीपी ने कहा कि जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी, तब पूरी पुलिस फोर्स ने निरंतर अग्रिम पंक्ति में रहकर काम किया। प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा, हमारे प्रत्येक अधिकारी और जवान ने निडर होकर गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन, प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी और बुजुर्गों की देखभाल करना सुनिश्चित किया। लॉकडाउन में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया व पुलिस के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते अब तक लगभग 3000 राज्य पुलिस कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से फ्रंटलाइन पर काम कर रहे 14 पुलिस कर्मियों को कोविड–19 के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी।

सुरक्षित है वैक्सीन

डीजीपी ने कहा कि कोरोना से जंग जीतने के लिए देश में 40 लाख से अधिक व्यक्तियों को पहले ही यह इंजेक्शन दिया जा चुका है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। डीजीपी ने समस्त पुलिस बल के साथ–साथ आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे इस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में आगे आएं और आने वाले दिनों में टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही अन्य को भी जागरूक करें ताकि किसी के मन में टीकाकरण को लेकर भ्रम की स्थिति न रहे।

ग्रेटा ट्वीट मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने टूलकिट क्रिएटर्स के खिलाफ 153A, 120B के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल, ग्रेटा ने किसानों के समर्थन वाले ट्वीट में सत्ताधारी भाजपा को फासीवाद पार्टी तक करार दिया था। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल, एक दिन पहले ग्रेटा ने किसान आंदोलन के समर्थन के लिए टूल किट जारी किया था। इसमें उनकी भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देने का भी खुलासा हुआ था।

ग्रेटा ने एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर किया ट्वीट

वहीं, ग्रेटा ने ट्वीट कर कहा, मैं अब भी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को समर्थन दे रही हूं। किस भी तरह की नफरत, धमकियां और मानवाधिकारों के हनन से इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला।

विदेशी हस्तियों के ट्विट

रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी उप राष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस समेत कई विदेशी हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए। वहीं, इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपील की है कि किसी भी विदेशी हस्ती को बिना तथ्य जांचे, इस मामले में अपनी राय नहीं रखनी चाहिए।

गृह मंत्री शाह बोले– दुष्प्रचार भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता

वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में ट्वीट किया, कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को डिगा नहीं सकता है! कोई भी दुष्प्रचार भारत को नई ऊंचाइयां छूने से रोक नहीं सकता है! दुष्प्रचार भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता, सिर्फ प्रगति ही यह कार्य कर सकती है। भारत प्रगति करने के लिए एकजुट है और एकसाथ है।

विदेश मंत्रालय का जवाब

इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा, कुछ बड़ी हस्तियों ने किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनीखेज हैशटैग के साथ टिप्पणी की। यह गैर जिम्मेदाराना थी। क्यों कि ये कानून संसद में चर्चा के बाद संवैधानिक तरीके से पास हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस तरह की टिप्पणी करने वाली हस्तियों से अपील करते हैं कि पहले वे सही तथ्यों की जांच करें, इसके बाद सोशल मीडिया पर संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रखें।

पृष्ट 1 का शेष

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शराब .....

'स्पेशल इंक्वायरी टीम' की रिपोर्ट से केवल आधा सच ही सामने आ सकता है। यह एक सार्वजनिक तथ्य है की कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान हरियाणा प्रदेश में दो बड़े 'शराब घोटाले' सामने आये, जिसमें चोर दरवाजे से औने पौने दामों पर बड़े स्तर पर शराब की बिक्री व तस्करी हुई और कुछ 'चहेतों' ने प्रदेश के सरकारी खजाने में आने वाले अरबों रुपए को अपनी जेबों में भरा।

सुरजेवाला ने कहा कि हमारा पहले से ही मानना रहा है की पूरी सरकार शराब घोटाले की लीपापोती और शराब माफिया व सरकार में बैठे लोगों के गठजोड़ पर पर्दा डालने में लगी है, ऐसे में असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई केवल हाईकोर्ट की देखरेख में होने वाली स्वतंत्र जाँच से ही संभव है। ऐसे में बिना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग के कोई भी 'स्पेशल इंक्वायरी टीम' हरियाणा शराब घोटाले के असली किंगपिनों और आकाओं से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं जूटा सकती, इसलिए पूरे मामले की हाईकोर्ट मॉनीटरड जाँच ही होनी चाहिए ताकि असली गुनाहगारों को पकड़ा जा सके।

व्याख्यान: 'सोशल पोजीशन ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी एंड वीमेन एज अम्बेसडर ऑफ कल्चर एंड मिथ"

सेजल
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

सेक्सुअल हरासमेंट सेल प्रभारी डॉ मीनाक्षी एवम महिला प्रकोष्ठ प्रभारी मिस कोमल गर्ग के नेतृत्व में दो विस्तार व्याख्यान का आयोजन करवाया गया, जिसका विषय 'सोशल पोजीशन ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी एंड वीमेन एज अम्बेसडर ऑफ कल्चर एंड मिथ" रहा! इस व्याख्यान के दौरान लगभग 70 छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मंच संचालन मिस प्रीति , असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विभाग द्वारा किया गया।इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में निशा, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग ,राजकीय महिला महाविद्यालय, अम्बाला से शामिल रही। उन्होंने अपने व्याख्यान के दौरान प्राचीन एवम आधुनिक भारत में महिलाओ की स्थिति पर चर्चा की ।उन्होंने बताया कि महिलाओं की स्थिति वैदिक काल से अब तक परिवर्तित होती आई है। प्राचीन काल में महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन वैदिक काल के बाद उनकी समाज मे स्थिति में बदलाव आने लगा ,जहां पर अनेक सामाजिक बुराइयां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जोहर आदि बुराइयों ने जन्म लिया। उन्होंने छात्राओं को महिलाओं की उस समय यथास्थिति के बारे में अवगत कराने के साथ–साथ उन्हें भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताया कि कैसे उनके निरंतर प्रयासों से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ जिसके फलस्वरूप उन्हें वोट करने का अधिकार मिला और बहुत सी प्रथाओं पर प्रतिबंध उनके प्रयासों के तहत लगाया गया । इस अवसर पर महाविद्यालय कार्यवाहक डा मीनाक्षी ने छात्राओं को कहा कि वे अभी से अपने भविष्य के बारे में योजना बनाना शुरू करें और सोचना शुरू करें कि उन्हें वास्तव में अपने जीवन से क्या चाहिए, और उन्हें क्या प्राप्त करना है,। अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मिस पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर ,अंग्रेजी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मिसेज बीरेंदर कौर,डॉक्टर श्रेष्ठा,डॉक्टर सीमा पांडे,मिस मोनिका, मिस्टर विनय पाठक आदि महाविद्यालय परिवार उपस्थित रहा।

पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन लुटे जाने का क्यों है डर?

बातों बातों में

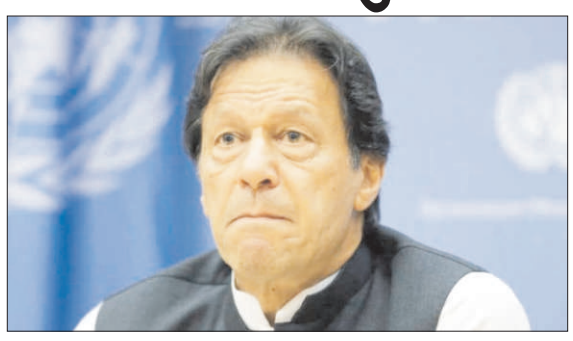

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने वाले कोरोना टीके का एक भी डोज पाकिस्तान अभी तक नहीं खरीद पाया है। चीन के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने पर भी उसे महज 5 लाख टीके का वादा मिला, जिसकी पहली खेप पाकिस्तान पहुंचने के बाद टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि, इस बीच पाकिस्तान को डर सता रहा है कि ये टीके उसके पाले आतंकियों की फौज ना लूट ले जाए। इस वजह से इन्हें अब गुप्त ठिकानों पर रखने को कहा गया है। सेना की तैनाती, सीसीटीवी से निगरानी सहित पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर (NCOC) ने कोरोना टीकों को चोरी और आतंकी हमलों से बचाने के लिए बुधवार को गाइडलाइन जारी की है। NCOC के मुताबिक, चाइना निर्मित कोरोना टीके सिनोफार्म को पाकिस्तान में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है और इसके लिए 1 फरवरी को देशभर के सभी प्रांतों में 70 हजार टीके भेजे गए हैं।

यहां से इन्हें सभी जिलों और शहरों के केंद्रों पर भेजा जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंटरपोल ने फर्जीवाड़े, चोरी और अवैध विज्ञापनों को लेकर अलर्ट जारी किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, जैसे कि आतंकवादी हमला या कोरोना टीकों को नकली टीकों से बदले जाने से रोकने के लिए टीकों के परिवहन, भंडारण और प्रशासन के लिए योजना बनाई गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना टीके ले जाने वाले वाहनों के साथ पुलिस, रेंजर्स या सेना का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही काफिले में अज्ञात सिक्यॉरिटी भी रहेगी। NCOC ने कहा है कि कोरोना टीके ले जाने वाले वाहनों के रूट को भी गोपनीय रखा जाए। साथ ही टीकों को भी अज्ञात स्थानों पर रका जाएगा, जहां कई स्तरों पर सुरक्षा होगी। सीसीटीवी, क्विक रिएक्शन फोर्स, पुलिस, रेंजर्स और सेना को तैना करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी प्रांतीय सरकारों से सिक्यॉरिटी बोर्ड बनाने को कहा गया है। वैसे तो हर देश में कोरोना टीकों की सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में यह डर ज्यादा है। क्योंकि एक तो यहां कोरोना टीकों की भारी कमी है और दूसरी तरफ आतंकियों और अपराधियों की बड़ी फौज है, जो अपनी जान बचाने के लिए टीकों को लूट सकते हैं। पाकिस्तान को चीन से 5 लाख टीके मिले हैं तो उसे कोवाक्स प्रोग्राम के जरिए अगले छह महीनों में 1.70 लाख टीके मिलने की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है और इमरान सरकार के पास टीके खरीदेने को पैसे नहीं हैं। ऐसे में यहां कोरोना टीकों की कब लूट हो जाए कोई नहीं जानता।

केंद्रीय बजट 2021–2022

कोविड-19 महामारी के बीच पेपर लेस बजट पेश

जानिए बजट के मुख्य बिन्दु

नई दिल्ली/ बातों बातों में

कोविड–19 महामारी के बीच पेश 2021–22 का केंद्रीय बजट काफी अलगा रहा। पहली बार पेपर लेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैब लेकर सदन में पहुंची और बजट पेश किया। बजटीय आंकड़ों के अनुसार 2020 के बजट के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था 2.24 लाख करोड़ सांकेतिक जीडीपी से घटकर 1.94 लाख करोड़ रुपये रह गई है। अर्थव्यवस्था के आकार में यह कमी राजस्व में गिरावट और वर्ष 2020 में अधिक व्यय के कारण हुई है। 2021–2022 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान था।

खर्च और घाटा

2021–2022 के लिए 83 लाख करोड़ रुपये बजट व्यय की आवश्यकता है। बजट व्यय 2021–2022 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8% होने का अनुमान है।

कर में छूट

कर विवादों को कम करना, निपटान को आसान बनाना: मामलों को फिर से खोलने के लिए समय सीमा 6 साल से 3 साल की गयी। 50 लाख या उससे अधिक रुपये की आय छुपाने के मामले को केवल प्रधान मुख्य आयुक्त की मंजूरी के साथ 10 वर्षों तक फिर से खोला जा सकता है।

सोना: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) सोने के एक्सचेंज के लिए नियामक होगा।

बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था: डिजिटल रूप से 95% लेनदेन करने वाली संस्थाओं के लिए कर लेखा परीक्षा के लिए टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गयी।

स्टार्टअप्स: स्टार्ट–अप्स के लिए कर अवकाश को एक वर्ष तक बढ़ाया गया। 31 मार्च, 2022 तक स्टार्ट–अप्स में निवेश के लिए पूंजीगत लाभ में छूट।

सीमा शुल्क: मोबाइल के कुछ हिस्सों पर सीमा शुल्क 'शून्य' दर से 5% तक बढ़ाया गया। गैर–मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील्स के उत्पादों पर सीमा शुल्क समान रूप से 5% तक कम किया गया। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क में 31 मार्च, 2022 तक छूट दी गई है। कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स, नायलॉन फाइबर और यार्न पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) घटाकर 5% किया गया। टनल बोरिंग मशीन पर अब 5%: सीमा शुल्क लगाया जायेगाय और इसके पुर्जों पर 2.5% शुल्क लगाया जायेगा। कपास पर सीमा शुल्क शून्य से 10% और कच्चे रेशम और रेशम यार्न पर 10% से बढ़कर 15% किया गया।

विनिवेश: 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी की बिक्री से 1,75,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

स्वास्थ्य: 6 वर्षों में पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। कोविड टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

शहरी विकास: 86 करोड़ घरों में नल के द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 0 को पांच वर्षों में लागू किया जाएगा, इसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। दो नई मेट्रो तकनीकें दृ मेट्रोलाइट और मेट्रोनेटो दृ का उपयोग टियर –2 शहरों और टियर –1 शहरों के परिधीय भागों में पारंपरिक मेट्रो सिस्टम की तुलना में कम लागत पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

वाहन: पुराने और अनफिट वाहनों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति। स्वचालित फिटनेस केंद्रों में प्रत्येक 20 वर्ष में व्यक्तिगत वाहनों और प्रत्येक 15 वर्ष में वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा।

विनिर्माण: आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 97 लाख करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइल्स पार्क (MITRA) योजना के तहत, 7 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे।

आधारभूत संरचना: 20,000 करोड़ रुपये एक वित्तीय वित्तीय संस्थान (क्थ्प्) की स्थापना की जाएगी, यह अधोसंरचना के विकास के लिए वित्त प्रदान करेगा।

रेलवे: 1,10,055 करोड़ रुपये का आवंटन |1,07,100 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए हैं। 2021–22 में, सरकार नेरेलवे से 17 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने का अनुमान रखा है।

हरित ऊर्जा: हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा

बीमा: बीमा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49: से 74: की गयी।

बैंकिंग: स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन: एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की जाएगी। सरकारी बैंकों का पुनर्पूंजीकरण: सरकारी बैंकों की वित्तीय क्षमता को और मजबूत करने के लिए 2021–22 में 20,000 करोड़ प्रदान किये जायेंगे।

कंपनी मामले: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपनी परिभाषा में संशोधन करके छोटी कंपनियों की अनुपालन आवश्यकता को आसान बनाने के लिए भुगतान की गई पूंजी के लिए अपनी सीमा50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ की गयी।

कृषि: कृषि साख का लक्ष्य बढ़ाकर ₹2021–22 में 5 लाख करोड़ किया गया |5प्रमुख मत्स्य पालन बंदरगाह- कोच्चि, चेन्नई, विशाखा पत्तनम, पारादीप, और पेटुघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा। राज्य द्वारा संचालित कृषि उपज विपणन समितियां (एपीएमसी) अब 1 लाख करोड़ के 'एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड' (एआईएफ) का उपयोग कर सकती हैं।

वरिष्ठ नागरिक: वरिष्ठ नागरिकों को राहत: 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गयी है।

अनुसन्धान व विकास: नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) के निर्माण के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है।

शिक्षा: लद्दाख के लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

पाइप लाइनों के जरिए गैस पहुंचाने की योजना से होगा फायदा

हरियाणा दुग्ध विकास संघ के चेयरमैन रणधीर सिंह ने कहा है कि बजट में युवाओं का खास ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की उज्ज्वला योजना और करीब एक करोड़ नए कनेक्शन घरों तक पहुंचाना बजट में बड़ा कदम है। चेयरमैन रणधीर सिंह ने कहा कि पाइप लाइनों के जरिए गैस पहुंचाने की योजना से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आप देश में कहीं भी राशन ले पाएंगे।

आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान

भाजपा जिला मीडिया सह प्रभारी अक्षय नंदा का कहना है कि आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। समाज के हर वर्ग के हित में यह बजट संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस बजट से देश का आम जन आर्थिक रूप से मजबूत होगा।

केंद्रीय बजट: मन की बात

बजट हवाई सपने दिखाने वाला: अरोड़ा

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा का कहना है कि सरकार बड़े–बड़े सरकारी उपक्रमों को अपने चहेते कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचने पर जुटी हुई है। इस बजट में महिलाओं युवाओं किसानों और व्यापारियों के लिए कोई राहत नहीं है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने तो बजट को हवाई सपने दिखाने वाला और आंकड़ों का मायाजाल बताया है।

बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं

जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पवन गर्ग का कहना है कि बजट में कर्मचारियों के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया पवन गर्ग ने कहा कि उन राज्यों को तोहफे दिए जा रहे हैं जिनमें हाल में चुनाव होने वाले हैं।

बजट सब्सिडी के नाम पर जनता से धोखा

कांग्रेस नेता सुभाष पाली ने कहा है कि भाजपा सरकार कॉर्पोरेट के हाथों गुलाम बनाना चाहती हैं बजट में सरकार का दिवालियापन झलक रहा है पेट्रोल डीजल गैस के दामों में वृद्धि सब्सिडी के नाम पर जनता से धोखा यही सब है बजट।

बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए नहीं उठाये ठोस कदम

इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन कांग्रेसी नेता जलेश शर्मा ने कहां है कि केंद्रीय बजट में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए। केंद्रीय बजट से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है।

बजट में किसान वर्ग हुआ निराश

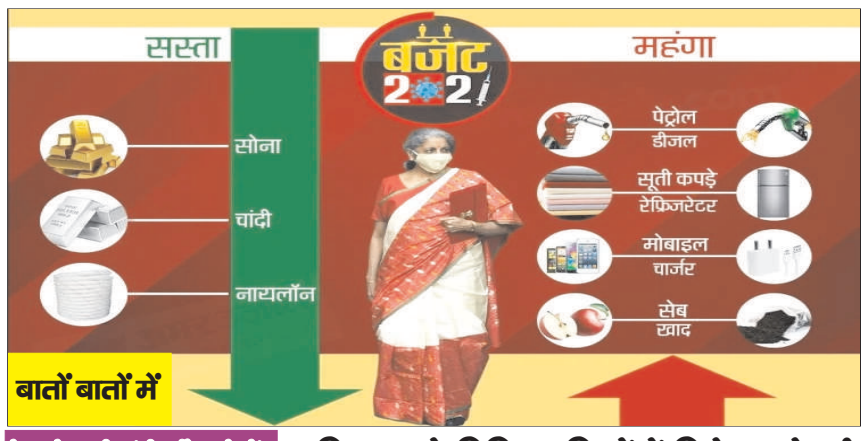

कुरुक्षेत्र अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जगतार सिंह काजल का कहना है कि आम बजट में किसान वर्ग को फिर निराश होना पड़ा है। वह भी ऐसे समय में जब की किसान पहले से ही 3 कृषि कानूनों को लेकर 2 महीनों से सड़कों पर आंदोलन करने पर मजबूर है।

बजट में आम जन को राहत देने लिए कोई नीति नहीं

पार्षद कांग्रेसी नेता नरेंद्र शर्मा निंदी का कहना है कि आखिर मोदी सरकार भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाएगी। क्योंकि आम आदमी का महंगाई के चलते जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है । बजट में आम जन को राहत देने लिए कोई नीति नहीं बनाई गई।

देश मे भारी मंदी और लोगों की नौकरियां छूट

जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार पिडारसी का कहना है कि देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है । देश मे भारी मंदी और लोगों की नौकरियां छूट रही है । ऐसे हालात में यह उम्मीद थी कि सरकार बजट में कोई खास विशेष कदम उठाएगी ताकि लोगों को राहत मिले लेकिन आमजन इस बजट से निराश हुआ है।

हरियाणा के विभिन्न जिलों में विशेष छापेमारी

चंडीगढ़रूहरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दूध उत्पादों, मसालों और चाय सरीखे खाद्य पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है, ताकि बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। पिछले छह महीनों में 1,62,94,120 रूपये का माल जब्त किया है। हाल ही में इस तरह की छापेमारी करने के लिए एक राज्य स्तरीय टीम का गठन किया है। जब्त किए गए नमूनों में से लगभग 28 नमूनों को असुरक्षित पाया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर उक्त चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया था और इसके सदस्यों में एक नामित अधिकारी और तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। घी, खाद्य तेल, दूध, दूध उत्पादों और अन्य खाद्य लेखों में मिलावट पर नजर रखने के लिए टीम नियमित रूप से हरियाणा के विभिन्न जिलों में विशेष छापेमारी कर रही है।

बजट आमजन के साथ धोखाधड़ी का बजट

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता महिमा सिंह का कहना है कि 2021 का बजट न सिर्फ आमजन के साथ धोखाधड़ी का बजट है बल्कि आज तक का सबसे अवसर वादी बजट है। करोना महामारी देश के जनजीवन पर पहले ही आघात कर रही थी, कई मध्यमवर्गीय उद्योग बंद हुए और बहुतायत में लोग बेरोजगार हुए, ऐसे में देश के नागरिकों की निगाह बजट पर ही होती है। मगर ये बजट तो बंगाल, तमिल नाडू व अन्य चुनाव बद्ध प्रदेशों को लुभाने के प्रयास के सिवाय कुछ भी नहीं है, जिसे वित्त मंत्री ने बंगाल के विशेष अवसरों पर ही पहने जाने वाली लाल पार की साड़ी पहन कर पेश किया है। पहले ही प्रधान मंत्री के परिवर्तित होते परिधान को तो हम निरंतर देख ही रहे हैं जो आजकल रबींद्रनाथ टैगोर की छवि में उतरने को प्रयासरत हैं। सरकार की दोहरी नीति प्रत्यक्ष है– चाहे वो इंटरनैट बंद कर पेपरलैस बजट पेश करने की हो या फिर कृषि सैस लगाकर कृषकों को महंगा डीजल खरीदने पर विवश कर देने की हो।

जो सरकार लोकतंत्र को किलेबंदी से चलाने का प्रयास करती है, वो उल्टी गिनती शुरू कर दे।

कंडेला से भरा किसानों में जोश

जींद की धरती से 19 साल बाद फिर उठी किसानों के हक की आवाज

जींद/बातों बातों में

हरियाणा के जींद जिला के गांव कंडेला की धरती से एक बार फिर किसान नेताओं ने किसानों में आंदोलन के प्रति जोश भरा। करीब 19 साल बाद बुधवार को फिर से जींद की इस धरती से किसानों के हक की अवाज उठाई गई। कंडेला खाप के साथ प्रदेश की अन्य खापों ने इस महापंचायत में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हरियाणा के कोने कोने से किसानों ने महापंचायत में पहुँच कर वक्ताओं को सुना। गौरतलब है कि आजकल भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बन कर उभर रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए हर जगह भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि वह स्वयं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरणे का नेतृत्व कर रहे हैं। बुधवार को कंडेला में आयोजित इस महापंचायत के मंच से बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राजा जब डरता है, तो किलेबंदी करता है।

दिल्ली बार्डर पर किसानों से डर कर सरकार किलेबंदी कर रही है। बार्डर पर तारबंदी की जा रही है और कीलें गाड़ी गईं। लेकिन इससे किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की मांग तीनों कृषि कानून वापसी की है। अगर बात गद्दी वापसी पर आ गई, तो सरकार क्या करेगी। टिकैत ने शांतिपूर्वक आंदोलन करने का आह्वान करते हुए कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती और एमएसपी की गारंटी नहीं देती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली कूच ना करें। टिकैत ने स्पष्ट किया कि सरकार से बातचीत के लिए जो 40 किसानों की कमेटी बनाई गई है, उसके सदस्य नहीं बदले जाएंगे। कमेटी भी वही रहेगी और इसके सदस्य भी वही रहेंगे। महापंचायत में तीन कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी का कानून के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार से बातचीत के लिए गठित किसानों की कमेटी के साथ बातचीत करने की मांग की गई।

टिकैत के खड़े होते ही गिर गया मंच

किसान महापंचायत के दौरान कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने राकेश टिकैत को संबोधन के लिए पुकारा तो जैसे ही टिकैत बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए, तभी मंच धड़ाम से गिर गया। मंच पर ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंच गई थी। आयोजकों द्वारा मंच पर पहुंचे लोगों से बार–बार नीचे उतरने की अपील की जा रही थी, लेकिन किसान नेता टिकैत से मिलने और फोटो खींचवाने के चक्कर में अत्यधिक भीड़ मंच पर पहुंच गई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। उस समय मंच

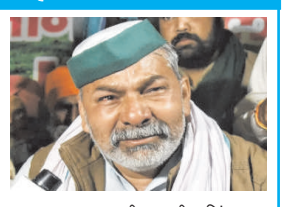

पर गुरनाम चढूनी, बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ. राजेंद्र सूरा समेत कई नेता बैठे थे। मंच गिरते ही खड़े लोगों ने किसान नेताओं को उठाया। आयोजक टेकराम कंडेला ने राकेश टिकैत को संभाला और खड़ा किया। टिकैत ने मंच से सब ठीक होने की घोषणा की।

चौपाल में रखी जाएंगी कीलें

टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगी हुई किलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये कीलें उखाड़ ली जाएंगी और चौपाल में रखी जाएंगी। ये कीलें आने वाली पुस्तों को दिखाई जाएंगी कि कैसे किसान लड़ाई जीता था। भाकियू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में तरह–तरह की यात्राएं निकाली जा रही हैं। राम मंदिर के नाम पर पैसा एकत्रित किया जा रहा है। किसान का राम उसके काम में बसता है। वह काम शुरू करने से पहले राम का नाम लेता है। हमारा राम किसी मंदिर या मूर्ति में

नहीं है। इन लोगों ने राम के पास पर दुकानें खोल ली हैं।

किसानों के लिए देंगे कुर्बानियां: गुरनाम

भारतीय किसान यूनियन (चढूनी गुट) के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि देश सैकड़ों कुर्बानियां देकर आजाद हुआ है। आज फिर काले कानूनों से आजादी के लिए लड़ाई चल रही है। किसान इसके लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। यह आंदोलन किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन आज पूरे देश का जन आंदोलन बन गया है। जितने कानून सरकार बना रही है, वह केवल पूंजीपतियों के लिए बना रही है। पहले देश सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह गया। यह सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अडानी, अंबानी 90 करोड़ रुपए कमाते हैं और इतना ही देश के किसानों पर कर्ज है। हर साल 3 से 4 लाख किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं।

कील बंदी करके बनाई खुली जेलें : राजेवाल

पंजाब के किसान नेता सरदार बलबीर सिंह राजोवाल ने कहा कि सबसे बड़ा योगदान देश के किसानों का है। यह पहला आंदोलन है, जिसे दुनिया देख रही है। अफसोस है कि मोदी सरकार किसानों से जैसा बर्ताव कर रही है, किसी देश की सरकार ने किसानों के साथ ऐसा नहीं किया। सरकार से 11 मीटिंग हुई। दिल्ली में कील बंदी गई है और बैरीकेड्स लगाए जा रहे हैं। किसी दुश्मन के लिए आज तक ऐसा नहीं किया गया। एक तरह से ओपन जेल बना दी गई है। महम के विधायक सोमबीर सांगवान ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है और लोग उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को कानून वापस लेने होंगे। इसके लिए हर घर से एक व्यक्ति को आंदोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।

दिल्ली के बॉर्डरों पर किलों से पहरा

पुलिस ने बनाए 'अंतर्राष्ट्रीय सीमा' जैसे हालत

रणदीप रोड़
नई दिल्ली/ बातों बातों में

केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के 3 बॉर्डर अब ऐसे लगते हैं कि भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बॉर्डर तो नहीं! जी हाँ, इन बॉर्डरों पर पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सहित भरी भरकम बैरिकेड लगाने के साथ सुरक्षा बढ़ा दी है। यही नहीं बॉर्डर पर सड़क में कीलें व नुकीले सरिये भी गाड दिये गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर पर सीमाओं के बंद रहने और आने–जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। पुलिस ने मुख्य राजमार्ग के किनारे सीमेंट के बेरिकेटों की दो कतारों के बीच लोहे की छड़ें लगा दी हैं। दिल्ली–हरियाणा राजमार्ग के एक अन्य हिस्से पर सीमेंट की अस्थायी दीवार बनाने से वह हिस्सा भी आंशिक रूप से बाधित हो गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, "गाजीपुर बॉर्डर बंद है। एनएच–24, रोड नंबर 56, 57ए, कोंडली, पेपर मार्केट, टेल्को टी प्वाइंट, इडीएम मॉल, अक्षरधाम और निजामुद्दीन खत्ता से यातायात को मोड़ दिया गया है। विकास मार्ग, आईपी एक्सटेंशन, एनएच–24 पर ज्यादा आवागमन है। मुसाफिरों को सलाह दी जाती है कि दूसरे बॉर्डर से आवाजाही करें। पुलिस के मुताबिक दिल्ली–गाजीपुर सीमा, किसानों के प्रदर्शन के कारण यातायात के लिए बंद है। यात्री आनंद विहार, चिल्ला, डीएनडी, अप्सरा, भोपुरा और लोनी बॉर्डर का रास्ता ले सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एक और ट्वीट में कहा कि सिंघु, सबोली, पियाऊ मनियारी बॉर्डर बंद हैं। औचंदी, लामपुर, सफियाबाद, सिंघू स्कूल और पल्ला टोल टैक्स बॉर्डर खुले हैं।

वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग–44 से भी यातायात को मोड़ दिया है और यात्रियों को बाहरी रिंग रोड, जीटीके और एनएच–44 से बचने की सलाह दी है। उधर इस बेरिकेटिंग व तारबंदी को लेकर किसानों का दोटूक अंदाज में कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे दिल्ली से वापस नहीं लौटेंगे। टिकरी बॉर्डर पर तमाम परेशानियों के बीच और दिल्ली में दाखिल होने से रोकने को लेकर पुलिस के किए गए इंतजाम किसानों के हौसले को पस्त नहीं कर पा रहे हैं।

जो चाहे कर लें, नहीं जाएंगे वापिस: किसान मोर्चा

किसान संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि किसानों को दिल्ली में रोकने के लिए पुलिस जो पैंतरे आजमा रही, किसान संयुक्त मोर्चा इसकी निन्दा करता है। हमारे हौसले में कोई कमी नहीं आई है। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा कि काले कानून को जब तक वापस नहीं करवाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। जिसे जो करना है कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। उधर किसान संगठन आंदोलन को और तेज करने के प्रयास में जुट गए हैं। किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देशभर में चक्का जाम करने का ऐलान किया।

राहुल बोले: सड़क पर दीवार नहीं पूल बनाए सरकार

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि सरकार को पुल बनाने चाहिए, दीवार नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनकी मांग का अस्वीकार करते हुए कहा कि सदस्य एक दिन बाद, बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा

सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि "आज गाजीपुर बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं, कील लगा दी गई हैं, जो पार्लिमेंट की सुरक्षा से भी ज्यादा है।

गाजीपुर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वह पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। मैंने पाकिस्तान बॉर्डर देखी है। क्या किसान दिल्ली हमला करने आ रहे हैं?

अंग्रेजों ने भी वापिस लिए थे कृषि बिल: आजाद

राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने तीनों कृषि कानूनों को फौरन वापस लेने की मांग की।

आजाद ने कहा, "मैं पीएम से निवेदन करता हूं कि तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाएं। अंग्रेजों ने भी ब्रिटिश इंडिया में एक बार नए कृषि कानून वापस लिए थे।

मैं पीएम से यह भी निवेदन करूंगा कि जो लोग 26 जनवरी से लापता हैं उनकी जांच के लिए कमेटी गठित हो। हम 26 जनवरी को हुई हिंसा की निंदा करते हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

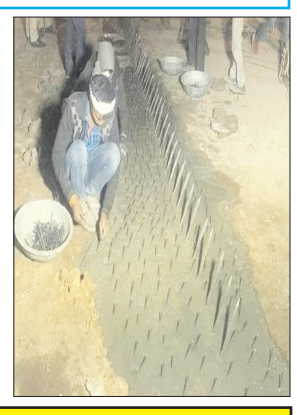

यूपी में भाजपा के लिए यह है चिंता का कारण

पश्चिमी यूपी के किसान इस आंदोलन की जड़ में हैं जो भाजपा के लिए चिंता की बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 20–22 सीटों पर यही वोटर हार–जीत तय करते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 के विधान सभा चुनावों में भाजपा को कुल 41 फीसदी वोट मिले थे जबकि पश्चिमी उत्तरप्रदेश में इसे करीब 44 फीसदी वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी यूपी में भाजपा को कुल 50 फीसदी वोट मिले थे जबकि पश्चिमी उत्तरप्रदेश में उसे 52 फीसदी वोट मिले थे। यानि जिस क्षेत्र में अब विरोध उभरा है वो भाजपा का गढ़ बन चुका था। हालांकि, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के शुरू में होने हैं, लेकिन भाजपा को उन चुनावों में इस आंदोलन के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगर किसानों ने आंदोलन लंबा खींचा तो भाजपा को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका असर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड पर भी पड़ सकता है. वहां भी 2022 में चुनाव होने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही किसानों का विरोध–प्रदर्शन झेल चुके हैं और उन्हें अपनी सभा रद्द करनी पड़ी है। डेढ़ साल पहले ही सत्ता पर कब्जा पाने वाले खट्टर की पकड़ वहां कमजोर होती दिखी। इसकी मुख्य वजह किसान आंदोलन ही है। हरियाणा में हालिया निकाय चुनावों में किसान आंदोलन की वजह से ही भाजपा और जेजेपी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा है। पंजाब में भी अगले साल विधान सभा चुनाव होने हैं। कृषि कानून के मुद्दे पर पहले से ही वहां एनडीए टूट चुका है। अब भाजपा और अकाली दल की राहें अलग हो चुकी है।

बीजेडी ने भी जताई नाराजगी

पहले इन बिलों पर सरकार के साथ खड़ी बीजेडी ने अब कहा है कि अगर इन कृषि बिलों को सलेक्ट कमेटी को भेजा जाता तो आसमान नहीं टूट पड़ता। बीजेडी के सांसद प्रसन्न आचार्य ने कहा, "अगर कृषि बिल पहले ही सलेक्ट कमेटी को भेजे गए होते तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। सुप्रीम कोर्ट को इस पर कमेटी गठित करनी पड़ी।मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह स्वामी नाथन कमीशन की रिपोर्ट सही तरीके से लागू करे।सरकार ने स्वामी नाथन कमीशन की रिपोर्ट ठीक से लागू नहीं की है। सरकार ने 2014 में कहा था किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन क्या 2020–21 में किसान की इनकम डबल हो गई है?"

86% छोटे किसानों के हक में हैं बिल बीजेपी

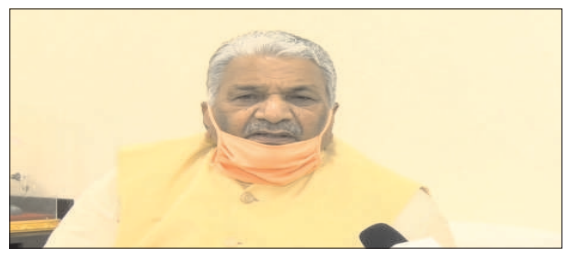

चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद विजय पाल सिंह तोमर ने दावा किया कि ये तीनों कानून 86 फीसदी छोटे किसानों के हक में हैं।

विजय पाल सिंह तोमर ने कहा, "नए कृषि कानूनों से छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा फायदा होगा। आज कृषि से इनकम बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है और नए कृषि कानून इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।"साथ ही तोमर ने कहा कि नए कृषि कानूनों के बारे में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा नहीं की गई, लेकिन पिछले 15 से 20 साल में 12 एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई हैं। 2010 में हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कमेटी बनी। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी जिसे 2014 तक लागू भी नहीं किया गया।

प्रगतिशील किसान क्लब

सतीश राणा

कस्टम हायरिंग सैंटर

कस्टम हायरिंग सैंटर में उपलब्ध कृषि यंत्रों का विवरण

• बेलर • हेरेक • हैप्पी सीडर • जीरो ड्रिल • रोटावेटर
• चोपर • रिवर्सिबल प्लो • रोटरी स्लैशट (कटर)

किसान भाई फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्र किराये पर चलवाने के लिए संपर्क करें।

मो: 98120-53339,70155-29951

नोट: पराली की गांठे बंधवाने के लिए बेलर का विशेष प्रबंध है।

वक्त के साथ बदल रहे हैं रहन–सहन और खान–पान के तरीके

विरासत

बदलते दौर में भी परिवारों को जोड़े रखने में अहम भूमिका निभा रहा है हरियाणा का "सांझा चूल्हा"

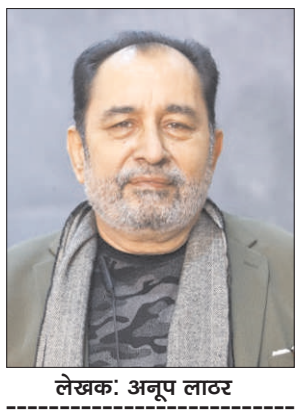

लेखक: अनूप लाठर

हरियाणा का अधिकतर भाग एनसीआर में पड़ता है जिस कारण यहां शहरीकरण का बहुत प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि पिछले 2 दशक में हरियाणा का रहन–सहन व खान–पान काफी बदला है। उत्तर में लघु हिमालय की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों तथा पूर्व में यमुना से लेकर पश्चिम में घग्गर नदी तक समूचे हरियाणा में हर चीज में बदलाव आया है।

इस सबके बावजूद "सांझा चूल्हा" आज भी हरियाणवी संस्कृति का अभिन्न अंग है। पहले जहां हरियाणा के बारे में प्रचाललित था कि "देशां मैं देश हरियाणा जित दूध दही का खाणा", वहीं अब दैनिक भोजन में दूध दहीं की मात्र काफी घटी है। इसके पीछे कारण है दूध को बेचना। लगभग सभी बड़ी दुग्ध डेयरियों कीगाड़ियां अथवा मोटर साइकिल पर दूधिये सुबह–शाम गांवों में आते हैं और दूध ले जाते हैं। इसके साथ ही खाने के अनाज में भी काफी परिवर्तन आया है। तकरीबन 3–4 दशक पहले हरियाणा के उत्तरी व उत्तर–पूर्वी भागों को छोड़ कर बाकी सारे ग्रामीण परिवेश में मोटे अनाज खासकर ज्वार–बाजरे की रोटी बनती थी। आज ये अनाज भोजन की थाली से उठते जा रहे हैं। गेहूं व चावल थाली में आ चुके हैं। इसका मुख्य कारण है मोटे अनाजों की खेती का घटना। अब आधुनिक तकनीक के द्वारा किसानों के पास पानी के संसाधन उपलबद्ध होने के कारण धान, गेहूं व गन्ने की खेती अधिक होने लगी है। अब तो बाजरा, मक्का व मिस्सी रोटी कुछ विशेष अवसरों पर अथवा सर्दियों के मौसम में ही बनती है। बाजरे की रोटी व खिचड़ी खासकर दक्षिणी हरियाणा में बनती है। उत्तरी हरियाणा के गावों का अधिकतर शहरी करण हो चुका है। हालांकि सर्दियों में मक्की की रोटी व सरसों का साग आज भी गांव–देहात में बड़े चाव से खाया जाता है। साग में मक्खन भी जरूर डाला जाता है। पहले हल–बैलों की खेती होती थी सो किसान अल सुबह बैल लेकर खेतों में चले जाते थे, और तकरीबन 10–11 बजे उनके लिए हजारी की रोटी जाती थी और उसके बाद शाम का खाना ही बनता था। आज मशीनी खेती के कारण किसान अक्सर सुबह का नाश्ता करके ही खेतों में जाते हैं। ऐसे में दोपहर व शाम का खाना भी बनने लगा है। पहले चाय का नामो–निशान नहीं था, लेकिन अब सुबह बैड–टी से लेकर नाश्ते के साथ चाय, इसके बाद 10 बजे की चाय और शाम को 4 बजे के करीब एक चाय अक्सर सभी घरों में बनती है। अगर पकवानों की बात करें तो आज भी हरियाणा के गांवों में बड़े चाव से हलुआ, पूरी, खीर, पूड़े, माल–पूड़े, गुलगुले, लापसी व मिट्ठी सवालियां बनाई जाती हैं। अधिकतर पकवान कुछ खास त्योहारों पर ही बनते हैं, जबकि घरों में मेहमान आदि आने पर हलुआ व सेवियां बनाना आम है। "सांझा चूल्हा" आज भी हरियाणवी संस्कृति का अभिन्न अंग है जो परिवार को जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि हरियाणा की परिवारिक व्यवस्था आज भी बहुत मजबूत है। "सांझा चूल्हा" आज भी हरियाणा के गावों की शान है। अधिकतर ग्रामीण परिवार आज भी संयुक्त परिवार व्यवस्था से रहते हैं। मिट्ठी के हारे और चूल्हे आज भी गांवों में देखने को मिल जाते हैं। अधिकतर घरों में मिट्ठी के चूल्हे पर पूरे परिवार की रोटी बनती है। सुबह, दोपहर व शाम का भोजन इन्हीं चूल्हों पर बनता है। हालांकि हरियाणा के गांवों के अधिकतर घरों में कुकिंग गैस आ चुकी है, लेकिन उसका इस्तेमाल पूरे परिवार का खाना बनाने के लिए अभी भी बहुत कम ही किया जाता है। "सांझा चूल्हा" व्यवस्था हरियाणा गांवों में ही नहीं अपितु शहरों में भी कायम है।

नोट: लेखक श्री अनूप लाठर हरियाणवी संस्कृति के ध्वजवाहक के तौर पर जाने जाते हैं और अनेकों विख्यात फिल्मों में भूमिका निभा चुके हैं।

डिब्बाबंद घी पर 'आईसीएआर–एनडीआरआई प्रौद्योगिकी' लिखे होने पर नोटिस जारी

चंडीगढ़:हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) करनाल को एक निजी कंपनी के डिब्बाबंद घी पर 'आईसीएआर–एनडीआरआई प्रौद्योगिकी' लिखे होने पर नोटिस जारी किया है।

विभाग ने हाल ही में मिष्ठी फॉर्मर निर्माता कंपनी लिमिटेड में छापेमारी की थी जहां अर्जुन हर्बल घी की पैकेजिंग जब्त की गई थी जिस पर एनडीआरआई करनाल का नाम लिखे होने पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। नाम के अलावा, घी समय सीमा समाप्त पंजीकरण के साथ बेचा जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर गठित स्टेट फ्लाइंग टीम ने मिष्ठी फॉर्मर निर्माता कंपनी लिमिटेड करनाल मे छापा मारकर वहां से 8,000 किलोग्राम मिलावटी घी जब्त किया था इसकी पैकेजिंग पर एक्सपायर रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख था। पंजीकरण 2019 में समाप्त हो गया था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ललित सिवाच ने कहा कि उन्होंने एनडीआरआई करनाल और संबंधित वैज्ञानिक से बात की है। तकनीकी कोलोब्रेशन के लिए ऐसा कोई समझौता नहीं है। औपचारिक एमओयू बहुत पहले समाप्त हो गया था। अब एनडीआरआई विभिन्न उल्लंघनों के लिए फर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है।

हरियाणा सरकार ने 'ए–क्लास' तहसीलदारों को नायब तहसीलदार (प्रशिक्षु) के पद पर किया नियुक्ति

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 'ए–क्लास' तहसीलदारों का एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आज उनको जिलों में नायब तहसीलदार(प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति दे दी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अनिल कुमार को कैथल जिला का नायब तहसीलदार(प्रशिक्षु) नियुक्त किया गया है। इनके अलावा, अजय हूडा को झज्जर, भूमिका लांबा को रेवाड़ी, ललिता को पानीपत, मंजीत मलिक, शुभम शर्मा व रिटा ग्रोवर को करनाल, निखिल सिंगला, आदित्य रंगा व धीरज कुमार पांचाल को पंचकुला, शिखा व सज्जन कुमार को गुरूग्राम, सृष्टि व मनोज कुमार को सोनीपत, विनति गोयल को हिसार तथा प्रियंका को कुरूक्षेत्र जिला का नायब तहसीलदार (प्रशिक्षु) नियुक्त किया गया है।

जिला अधिकारी मंगलवार को नारनौल की बजाए महेन्द्रगढ़ कार्य करेंगे

बातों बातों में

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि महेंद्रगढ़ जिला के सभी जिला स्तरीय अधिकारी, जिनकी नियुक्ति नारनौल में है, वे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को नारनौल की बजाय महेंद्रगढ़ में कार्य करेंगे। अगर मंगलवार को अवकाश होता है तो वे अधिकारी अगले कार्य दिवस पर महेंद्रगढ़ में कार्य करेंगे। सप्ताह में एक दिन महेंद्रगढ़ कार्य करने वाले इन अधिकारियों को हरियाणा सिविल सर्विसिज रूल्ज(टीए),2016 के रूल 58 के तहत जो टीए/डीए स्वीकार्य होगा, वह दिया जाएगा। राज्य सरकार के ये निर्देश तुरंत प्रभाव से माने जाएंगे।

हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बड़े पैमाने पर चलाया अभियान

बातों बातों में

चंडीगढ़:हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दूध उत्पादों, मसालों और चाय सरीखे खाद्य पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है, ताकि बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

पिछले छह महीनों में 1,62,94,120 रूपये का माल जब्त किया है। हाल ही में इस तरह की छापेमारी करने के लिए एक राज्य स्तरीय टीम का गठन किया है। जब्त किए गए नमूनों में से लगभग 28 नमूनों को असुरक्षित पाया गया।स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर उक्त चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया था और इसके सदस्यों में एक नामित अधिकारी और तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं।

स्घी, खाद्य तेल, दूध, दूध उत्पादों और अन्य खाद्य लेखों में मिलावट पर नजर रखने के लिए टीम नियमित रूप से हरियाणा के विभिन्न जिलों में विशेष छापेमारी कर रही है।

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि खाद्य मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। अरोड़ा ने बताया कि हाल ही में करनाल से 42 लाख रुपये का 8,400 लीटर घी, 57,41,500 रुपये का 11,483 लीटर देसी घी, हिसार से 15 लीटर शुद्ध घी व 17,000 लीटर वानस्पती का मूल्य 42,50,000 रुपये का जब्त किया है। अरोड़ा ने बताया कि इस वर्ष की शुरूआत में 98 लीटर मिलावटी श्री मदुर रतन देसी घी, 642 लीटर मिलावटी हरियाणा फ्रेश एगमार्क देसी घी, 3,276 लीटर केदार एगमर्ड मिश्रित वनस्पति तेल,1,145 लीटर हरियाणा फ्रेश एगमार्क देसी घी और श्री गोबिंद एगमार्क देसी घी अम्बाला से 4.58 लाख रुपये मूल्य की जब्त किया गया है।

साथ ही कुरुक्षेत्र से 12,97,820 रुपये का 19,645 लीटर मिलावटी घी, मक्खन, सुभम घी, अभिनंदन घी, क्रीम, पामोलिव ऑयलऔर मिल्क पाउडर जब्त किया गया और करनाल से 3,46,800 रुपये का 1,250 लीटर घी, मक्खन, खाद्य तेल जब्त किया गया।

खाद्य और औषधि प्रशासन के आयुक्त ललित सिवाच ने कहा कि हाल ही में छापे के दौरान हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से 500 नमूने जब्त किए गए थे।

इन 500 नमूनों में से 171 नमूनेखाद्य सुरक्षा और मानकों के अनुसार नहीं थे और एफएसएस (खाद्य सुरक्षा और मानक) अधिनियम, 2006 के अनुसार मानकों की पुष्टि नहीं की गई थी। 171 नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार खाद्य विश्लेषक ने पाया कि 28 नमूने असुरक्षित, 99 घटिया और 44 मिस ब्रांडेड थे। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष 28 असुरक्षित नमूनों के लिए खाद्यव्यवसाय संचालक के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है और शेष 143 नमूनों में, घटिया और गलत पाया गया है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार अधिकारियों के समक्ष मामले दर्ज किए जाएंगे।

सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरन्तर कार्य कर रही

बातों बातों में

चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। हरियाणा के लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (स्फैक) ने निजी कंपनियों के साथ सिरसा जिले के किसानों की 700 मीट्रिक टन किन्नू की फसल की खरीद हेतु इस वर्ष के लिए अनुबंध कराया है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया जा रहा है ताकि किसान समूह बनाकर अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त कर सकें। कृषि मंत्री हरियाणा ने बताया कि अब तक राज्य में कुल 486 किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ) का गठन करते हुए इन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत करवाया जा चुका है। इन किसान उत्पादक संगठनों के साथ 76000 से भी अधिक किसानों को जोड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नई एफ.पी.ओ. नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2021–22 तक एफ.पी.ओ गठन के लक्ष्य को 1000 तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि इन नए एफ.पी.ओ का गठन राज्य में कलस्टर निर्माण के आधार पर किया जायेगा। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह ने बताया कि जहां किसान उत्पादक संगठन बनाकर किसानों को एक साथ खेती करने के लिए तैयार

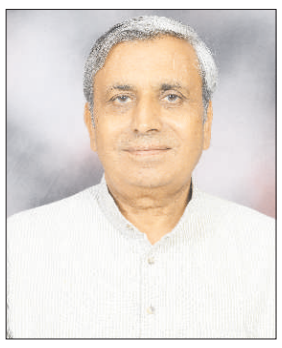

किया जाता है, वहीं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (स्फैक) का उद्देश्य उनकी फसल का उचित भाव किसान उत्पादक संगठनों को दिलाना है। स्फैक का कसानों को खाद, बीज सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने का प्रयास रहता है। उन्होंने बताया कि 15 एफ.पी.ओ. के प्रोजेक्टों पर कार्य निरंतर जारी है। इन प्रोजेक्टों पर 45.64 करोड़ रुपये का अनुदान जारी करने का अनुमान है।

इन प्रोजेक्टों की स्थापना के उपरांत राज्य के बागवानी किसान अपने उत्पादन की अच्छी प्रकार से ग्रेडिंग, पैकिंग व मूल्य संवर्धन उपरांत अपने एफ.पी.ओ. के माध्यम से देश में भिन्न–भिन्न स्थानों एवं व्यापारियों को फसल बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।

हाई कोर्ट का नोटिस 1500 पेंशनर्स को एरियर के 15 करोड़ न देने के चलते मिला नोटिस

कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

हाईकोर्ट ने अब कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय को नोटिस जारी किया है। पेंशनर्स की ओर से रुका हुआ एरियर पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 1500 से अधिक पेंशनर्स को तीन साल से 19 माह के 7वें वेतन आयोग के एरियर का पैसा न मिलने के मामले में हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय को नोटिस दिया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया था कि 19 अक्टूबर तक यूनिवर्सिटी प्रशासन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पेंशनर्स के एरियर के मामले में विचार करके लिखित आदेश पारित करे। कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय प्रशासन की ओर से बजट न होने की बात हाईकोर्ट के सामने रखी गई थी। इसपर पेंशनर्स दोबारा हाईकोर्ट चले गए 25 जनवरी को मामले में सुनवाई हुई।इममें 17 मार्च 2021 के लिए हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। एक जनवरी 2016 से एक सितंबर 2017 तक का एरियर: सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग को कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2016 से लागू किया था। केयू प्रशासन की ओर से एक सितंबर 2017 को 19 माह बाद पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ी पेंशन देनी शुरू की गई। इस हिसाब से पेंशनर का 19 माह का एरियर यूनिवर्सिटी पर बकाया हो गया। यह राशि करीब 15 करोड़ की है। इस एरियर में कर्मचारियों को उनके मासिक बढ़े वेतन के अनुसार 19 माह का लाभ मिलना है। पेंशनर्स ने कहा कि तीन साल गुजर चुके हैं। अब तक यूनिवर्सिटी की ओर से पेंशनर्स को उनका हक नहीं दिया जा रहा। यह पूरी तरह से अन्याय है। तीन साल तक इंतजार करने के बाद पहुचे हाईकोर्ट रू कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त असिस्टेंट रजिस्ट्रार देवेंद्र सचदेवा ने बताया कि फिजिक्स विभाग से सेवानिवृत्त जीपीएस गिल ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

जिसमें वे भी उनके साथ शामिल हैं। देवेंद्र सचदेवा ने कहा कि एरियर पाने की मांग को लेकर कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को पेंशनर्स ने ज्ञापन सौंपे। इतना ही नहीं कुलपति से भी जाकर मिले। इसके बावजूद उन्हें एरियर का लाभ नहीं दिया गया। इसके चलते न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। पेंशनर्स ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द उन्हें एरियर का लाभ दे।

वित्त विभाग को भेजा मामला

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोकसंपर्क विभाग के निदेशक प्रो. ब्रजेश साहनी ने बताया कि पेंशनर्स को एरियर का पैसा देने के लिए बजट का प्रबंध करने के लिए वित्त विभाग को मामला भेजा हुआ है।

रिपोर्ट कार्ड गॉंव झांसा

लिंगानुपात की असमानता मिटाने वाली हरियाणा की अग्रणीय ग्राम पंचायत झांसा 2016 में लिंगानुपात 624 व 2020 में 1333

- गांव में कैमिस्टों की दुकानों पर गर्भपात कीटो पर प्रतिबंध
- डॉ भीमराव अंबेडकर पार्क का निर्माण।
- डॉ भीमराव भवन निर्माणाधीन।
- डॉ भीमराव अंबेडकर चौक का निर्माण।
- गांव में कम्युनिटी हॉल का निर्माण।
- मारकंडा नदी पर जाल लगवाना।
- एसवाईएल नहर पर जाल लगवाना।
- पाल समाज की चौपाल।
- कश्यप समाज की चौपाल।
- बाल्मीकि समाज के चौपाल।
- गांव में कूड़ा उठाने का प्रबंध रेहडी द्वारा।
- गांव की सभी गलियों को पक्का करवाना।
- खेतों के रास्ते बनवाना।
- शहीद मदन लाल ढींगरा ग्राम सचिवालय का निर्माण करवाना।
- सभी सुविधाएं एक छत के नीचे सीएससी सेंटर।
- गांव में पटवार भवन की सुविधा।
- गांव में फूड सप्लाई ऑफिस की सुविधा।
- गांव में एग्रीकल्चर ऑफिस की सुविधा।
- गांव में पंचायत ऑफिस ऑफिस की सुविधा।
- गांव में रेस्ट हाउस ऑफिस की सुविधा।
- बच्चों के खेलने के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड का निर्माण।
- लाइटों के साथ पंचायत घर में पार्क का निर्माण।
- गांव के चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगवाना।
- गांव में टॉयलेट का निर्माण ।
- सरकारी स्कूल के सभी कमरों में कूलर लगवाना।
- सरकारी स्कूल में लाइटें लगवाना।
- सरकारी स्कूल में बैठने की व्यवस्था।
- स्कूल के ग्राउंड में मिट्टी से फिलिग।
- खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम सेगैस वितरण।
- सभी डेरो के रास्ते पक्के करवाना।
- गांव में RO की सुविधा।
- महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करना
- सर्व धर्म के लिए सीन उपलब्ध करवाना
- स्व. सेठ प्रेम चंद गर्ग बस स्टैंड का निर्माण

पुनीत मल जसुजा समाजसेवी

मीनू मल सरपंच झांसा

कविता

अफसोस

बहुत कुछ होने का दावा करते थे तुम
जब हम थे तेरे साथ
हमें ठुकराया है तुमने
एक अफसोस ही तो बचा है
अब तुम्हारे पास
बातों से बेरुखी छलकने लगी
होने लगा था गैरों सा अहसास
नजरों से गिरा दिया
कैसे जला पाओगे
अपनी रूह का लिबास
बिन जल के जैसे तड़पती है मछली
वैसा ही है अब कुछ तुम्हारा हाल
समंदर को बना लो
बेशक आशियाना अपना
मिट न सकेगी तुम्हारी प्यास

शिखा शर्मा स्वरचित
@copyright

हिंदी मासिकसमाचार पत्र बातों बातों में खबरे व विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें।
7015296154
हमारे साथ जुड़ने के लिए
batonbatonmein.com
facebook: baton baton mein....
(your city name)
watch on you tube: baton baton mein

कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास में एनसीसी का अहम योगदान : ब्रिगेडियर एएस बरार

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10 हरियाणा बटालियन द्वारा पांच दिवसीय एनसीसी कैंप का आयोजन

कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय स्थित 10 हरियाणा एनसीसी बटालियन द्वारा पांच दिवसीय एनसीसी कैम्प के आयोजन अवसर पर अंबाला ग्रुप कमांडर के ब्रिगेडियर एएस बरार (विशिष्ट सेवा मेडल) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

10 हरियाणा बटालियन एनसीसी कुरुक्षेत्र के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रूपेंदर सिंह के द्वारा बी और सी सर्टिफिकेट कार्यक्रम के दौरान ब्रिगेडियर एएस बरार ने कैंप में एनसीसी कैडेट्स की विभिन्न कक्षाओं में जाकर उनका निरीक्षण किया। विभिन्न कक्षाओं में कैडेट्स को अहम जानकारियां प्रदान देते हुए कहा कि एनसीसी उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उनका मानसिक व व्यक्तित्व विकास इससे और भी ज्यादा निखरेगा। अपनी निष्ठा लगन व मेहनत से आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम है कोई भी कार्य आज असंभव नहीं है इसके लिए आपको सकारात्मकता, धैर्य और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है, फिर मंजिल आप से दूर नहीं है। कैंप के दौरान ड्रिल, मैप–रीडिंग की जानकारी दी गई। कैंप में आईआईएचएस समेत विभिन्न महाविद्यालयों के 250 कैडेट्स भाग ले रहे हैं।

एनसीसी कैडेट्स बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डीएस रावत ने भी कैडेट्स को एनसीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। एसएसबी की जानकारी भी सेवानिवृत्त सूबेदार रविंदर और मनोज कौशिक के द्वारा कैडेट्स को महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया गया। जो आगामी भविष्य में सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर कैंप में एनसीसी अधिकारी कैप्टन अनुज, कैप्टन सुधा शर्मा, लेफ्टिनेंट सुकर्मवती, लेफ्टिनेंट सुरेश कुमार व लेफ्टिनेंट नीरज उपस्थित रहे। विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बटालियन के 4 जेसीओ 10 एनसीओ भी शामिल रहे।

अपने घर,उधोग और व्यवसाय के वास्तु दोष को आप कैसे पहचाने ?

कॉस्मिक एस्ट्रो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड़ के डायरेक्टर व श्री दुर्गा देवी मन्दिर पिपली (कुरुक्षेत्र) के अध्यक्ष ज्योतिष और वास्तु आचार्य डॉ. सुरेश मिश्रा ने बताया कि भवन निर्माण एवं वास्तु विज्ञान दो अलग–अलग विषय है। एक व्यक्ति अपने मनोनुकूल गृह का निर्माण तो करवा सकता है, अपने आर्किटेक्ट या डिजाइनर से कहकर उसे अच्छी प्रकार से सजा भी सकता है परन्तु वह उसमें रहने पर सुखी जीवन व्यतीत करेगा यह आवश्यक नहीं।

एक आर्किटेक्ट भी जिसे केवल भवन निर्माण तकनीक का ज्ञान है उस व्यक्ति के सुखी व मंगलमय जीवन की गारंटी कैसे ले सकता है परन्तु वास्तु विज्ञान एवं वास्तु के अनुरूप मकान का निर्माण करने से वास्तु विशेषज्ञ द्वारा शुभता लाई जा सकती है। मनुष्य यह सोचने पर विशेष मजबूर हो जाता है कि पहले मकान में ऐसा क्या था जो मैं सुखी व सन्तुष्ट था तथा धन संग्रह कर अपना स्वयं का घर बनाया तो मैं संकटों से घिर गया। यहां उस मकान, उधोग या व्यवसाय स्थल की वास्तु का बहुत अधिक प्रभाव उस के पारिवारिक जीवन पर होता है परन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि आप कैसे जाने कि जिस भवन में हम रह रहें हैं उसकी वास्तु हमारे अनुरूप है? यदि अनुरूप है तो वह हमारे तथा हमारे परिवार के लिये लाभकारी होगा क्या? यह लाभकारी घटक निम्नलिखित में से किसी भी रूप में हो सकता है:

- *भवन,उधोग और व्यवसाय स्थल में रहने से धर्मलाभ होना चाहिए तथा उस स्थान में रहने वाले प्राणी को अध्यात्मिक एवं आत्मिक सुख की अनुभूति होनी चाहिए।*
- *आपको दैविक एवं भौतिक उपसर्गों से मुक्ति मिलनी चाहिए।*
- *परिवार और आपका समाज में मान–सम्मान बढ़ना चाहिए।*
- *परिवार के दूसरे सदस्य भी सुख–शांति का अनुभव करें तो समझना चाहिए की उस भवन,उधोग और व्यवसाय स्थल की वास्तु गृहस्वामी के अनुरूप है।*
- *यदि गृह, उधोग या व्यवसाय स्वामी के व्यवसाय में उन्नति हो तथा उसके धन–धान्य में वृद्धि हो।*
- *यदि गृह, उधोग या व्यवसाय स्वामी कर्जदार है और उसका कर्ज धीरे–धीरे कम होना आरंभ हो गया है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है।*
- *गृह,उधोग या व्यवसाय स्वामी की आय के साधनों में वृद्धि होना प्रारम्भ हो जाये।*
- *यदि परिवार के सदस्य गृहस्वामी की आज्ञा में रहने लगें तो यह भी यही दर्शाता है कि घर,उधोग या व्यवसाय स्थल की वास्तु गृहस्वामी के अनुकूल है।*
- *परिवार के सदस्य यदि अध्यात्मिक एवं आत्मिक उन्नति करने लगें और मोक्षमार्ग का रास्ता प्रशस्त हो तो इसमें भी वास्तु शास्त्र की सार्थकता है।*

अब देखते हैं कि घर, उधोग या व्यवसाय सिल की वास्तु अनुरूप न होने के कारण कुटुम्बजनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है :

- *परिवार में और कर्मचारियों में झगड़ा व कलह अचानक आरंभ हो जाता है।*
- *आपका व्यय व्यर्थ ही बढ़ जाता है।*
- *परिवार के सभी सदस्यों की आमदनी में कमी हो जाती है।*
- *गृह स्वामी आर्थिक रूप से निर्बल हो जाए तो समझें उस घर,उधोग या व्यवसाय स्थल की वास्तु अनुकूल नहीं है*
- *अचानक कोर्ट केस हो जाए और व्यक्ति को मानसिक तनाव रहे तो समझें कि घर,उधोग या व्यवसाय सिल में वास्तु दोष है।*
- *उद्योगस्वामी,व्यवसाय स्वामी, गृहस्वामी का सम्मान समाज में कम होने लगें।*
- *अचानक सन्तति का नाश हो या फिर उसके बच्चे व कुटुम्बजन ,कर्मचारी उसकी आज्ञा का पालन न करें तो समझें की घर में वास्तुदोष है ।*
- *आपके परिवार में अकाल मृत्यु होना भी वास्तुदोष की सूचक है।*
- *अक्समात परिवार के सदस्यों को या कर्मचारियों को कोई रोग घेर ले तो समझें कि भवन,उधोग या व्यवसाय की वास्तु अनुकूल नहीं है।यदि आपको अनुभव हो कि घर में कुछ भी उपरोक्त में से घट रहा है तो समझ लेना चाहिए कि भवन में,व्यवसाय में और उधोग में धरती की नकारात्मक ऊर्जा अर्थात जिओपेथिक रेडिएशन दोष,पिशाच दोष,बन्धन दोष ,नजर दोष और वास्तुदोष आदि है और उसके निवारण हेतु यथा संभव वास्तुदोष निवारण के उपाय जिओपैथिक विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ के निर्देशन में भगवान में आस्था रख कर श्रद्धा पूर्वक ही करने चाहिए तभी लाभ होता है अन्यथा नुकसान होता है। आप कभी भी धन से भगवान को नहीं खरीद सकते है क्योंकि वो परमेश्वर आपके श्रद्धा भाव को देखते है।*

डॉ. सुरेश मिश्रा

हनुमान जी की उपासना से भक्तों से दूर होते है सभी कष्ट

कलयुग में सबसे जागृत देवता हैं हनुमान

भारतीय सनातन धर्म में सभी देवी–देवताओं की पूजा अर्चना करने का अपना–अपना महत्व बतलाया गया हैं। सनातन परंपरा के अनुसार मंगलवार को भगवान हनुमान जी की पूजा–आराधना का दिन माना गया है। बजरंगबली भगवान शिव के ग्यारहवें रूद्र अवतार माने जाते हैं।

इसलिये ही उनके अंदर असीमित शक्तियां हैं। भगवान शिव ने श्री राम अवतार के समय उनकी सहायता करने के लिए ही अपने एकादश रूद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में अंशावतार लिया था। हनुमानजी इस कलियुग में सबसे ज्यादा जाग्रत और साक्षात हैं। कलियुग में हनुमानजी की भक्ति दुख और संकट से बचाने में सक्षम हैं। हनुमान जी अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई भी भगवान श्री राम का नाम लेता है, हनुमान जी की सहज कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। हनुमानजी की कृपा जिस जातक पर बरसरना शुरू होती है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।

दस दिशाओं और चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति बजरंगबली जी की आरधना करता हैं तो उनके सभी संकट कट जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए भगवान श्रीराम के आदेश का पालन करते हुए पृथ्वीलोक में वास कर रहें हैं। मान्यताओं के अनुसार भक्तों के सभी कष्ट हनुमान जी की पूजा–उपासना करने से दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा से भक्तों की बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण हो जाता है। भक्तों की धन, विजय और आरोग्य की प्राप्ति हनुमान जी की कृपा से सहज ही हो जाती है। तो आपको कुछ विशेष पूजा और उपाय बतलाते हैं। भूत–पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंगबाण का पाठ करना चाहिए। नित्य रूप से हनुमान मंदिर में जाकर हनुमानजी की पूजाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपकी फैक्ट्री या व्यवसाय आदि पर भूत–प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े तो इसके लिए अपने–अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान ध्वज (झंडा) लगानी चाहिए।

ज्योतिष पंडित पवन शर्मा

घर के अंदर बुरी आत्माओं का प्रवेश न हो, इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम–राम लिखकर 7 बिंदु लगा दे जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा।

मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडहर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमत–ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का भय है तो आप 'हं हनुमंते नमः' का रात को सोने से पूर्व हाथ–पैर और कान–नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाएं।

कुछ ही दिनों में धीरे–धीरे आपमें निर्भीकता का संचार होने लगेगा। हर मंगलवार को हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। रोजगार प्राप्ति के लिए पान का बीड़ा नियम से मंगलवार को चढ़ाना चाहिए। इस उपाय से नौकरी मे भी उन्नति होती है। हनुमान जी गुलाब की माला मंगलवार शाम को अर्पित करें हनुमान जी की कृपा से भक्तों को धन प्राप्त हो जाता हैं। बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद मंगलवार के दिन शाम को व्रत करके हनुमान जी को भोग लगाएं। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं।

फीचर डेस्क बातों बातों में

पेड़ो के बारे में रोचक तथ्य

- दुनिया भर में पेड़ो की लगभग 23000 प्रजातियां पाई जाती है।
- एक पेड़ पूरे साल में लगभग 2000 लीटर पानी धरती से सोख लेता है।
- रोजाना जो आप न्यूज पेपर पढ़ते है उसका एक संस्करण बनाने में लगभग 500 पेड़ो का इस्तेमाल होता है। और आप जो किताबें पढ़ते है वो भी एक पेड़ का हिस्सा है।
- पूरे विश्व भर में भारत मे सबसे च्यादा पेड़ो की प्रजातियां पाई जाती है और बाद में अमेरिका आता है।
- केले का पेड़ लगभग 20 फीट तक बढ़ जाते है।
- चीन में लगभग 20 फीसदी पेड़ औषधियां बनाने में उपयोग किया जाता है।
- आपको बता दे कि पेड़ कभी भी बूढ़े होने की वजह से नहीं मरते है, ये किसी बीमारी या इंसानो द्वारा कटाई करने से मरते है।
- एक अनुमान के मुताबिक शहरों में उगने वाले पेड़ गावों में उगने वाले पेड़ों के मुकाबले 23 वर्ष कम जीते है, वजह तो आप समझ ही गए होंगे।
- पेड़ हमारी वातावरण में मौजूद कार्बन डाईऑक्साइड की अवशोषित कर लेते है इस प्रकार से ये हमे ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाते है इसलिये हमे
- पेड़ों को बचाना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय मे ये धरती इंसानो के रहने लायक नहीं रह पाएगी।
- पेड़ों को अपने घरों के आसपास लगाने से हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और पेड़ों के द्वारा छोड़ी ऑक्सीजन गैस से हम जिंदा है।

अंत मे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा पेड़ लगाइये क्योकि पेड़ हमारे लिए बहोत ही जरूरी है और इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।

बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व

वसंत पंचमी या श्रीपंचमी हिन्दू संस्कृति का त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनायी जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन छह मौसमों में बाँटा जाता था ।

उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूँ की बालियाँ खिलने लगतीं, आमों के पेड़ों पर मांजर आ जाता और हर तरफ रंग-बिरंगी तितलियाँ मँडराने लगतीं। भर भर भंवरे भंवराने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के पाँचवे दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती हैं। यह वसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता था। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों-शास्त्रों तथा अनेक काव्यग्रंथों में भी अलग-अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है।

बसंत पंचमी के धार्मिक व अन्य महत्व.....

बसंत पंचमी ओर मौसम

इस साल यह त्योहार 16 फरवरी दिन मंगलवार को है। बसंत पंचमी का उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में काफी उत्साह से मनाया जाता है।

माघ माहीने के पांचवे दिन बसंत पंचमी पड़ती है और इस दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है। हालांकि इस दिन मुख्य रुप से मां सरस्वती की पूजा करने का विधान है लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदेव और इनकी पत्नी रति धरती पर आते हैं और प्रकृति में प्रेम रस का संचार करते हैं इसलिए बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों में पूर्वाह्न से पूर्व सरस्वती पूजन करने का नियम बताया गया है।

इसलिये मनाई जाती है बसंत पंचमी

पौराणिक मान्यता के अनुसार, सृष्टि के रचियता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की है। लेकिन सृष्टि की तरफ जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी को चारों तरफ सुनसान और शांत माहौल नजर आता है। इसलिये उन्हें महसूस होता है कि, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जिसे देखकर ब्रह्मा जी मायूस हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया की और विष्णु जी ने कमंडल से पृथ्वी पर जल का छिड़काव किया और उस जल के द्वारा पृथ्वी हिलने लगी। पृथ्वी के हिलने के बाद एक अद्भुत शक्ति मां सरस्वती के रुप में प्रकट हुई। देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है और वहीं अन्य हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का निवेदन करते हैं इस तरह देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव-जंतुओं को आवाज मिल जाती है। वह दिन बसंत पंचमी का दिन था और तभी से देवी सरस्वती के जन्मदिवस के रूप में यह पर्व मनाया जाता है।

बसंत पंचमी का पौराणिक महत्व

हिंदू धर्म में माघ मास का बहुत अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि इस माह में कई महत्वपूर्ण पर्व और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख व पावन त्योहार पड़ते हैं। खासकर बसंत पंचमी का त्योहार, इस पावन दिन देवी सरस्वती के अवतरण दिवस के रुप में मनाया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। बसंत पंचमी सिर्फ इसलिये ही नहीं बल्कि कई अन्य मायनों में भी बहुत महत्व रखता है।

ज्योतिष के मुताबिक वसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहर्त के तौर पर जाना जाता है और यही कारण है कि नए काम की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है।

वसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना भी शुभ होता है। इतना ही नहीं, इस दिन पीले पकवान बनाना भी काफी अच्छा माना जाता है।

शहरवासियों का अपना होगा अंतराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव: एसडीएम

महोत्सव में योगदान होगा शहरवासियों के लिए अनिवार्य, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों का रहेगा महोत्सव में अहम सहयोग

बातों बातों में

पिहोवा: अंतराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में शहरवासियों के साथ–साथ देश–विदेश के श्रद्धालु व पर्यटक बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।

हर वर्ष अंतराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाता रहा है। परंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कुछ सीमाओं के अतंर्गत इस महोत्सव को मनाया जाएगा तथा ज्यादा भीड़ एकत्र न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। एसडीएम सोनू राम वीरवार को अपने कार्यालय में सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।एसडीएम सोनू राम ने बताया कि 16 फरवरी को पिहोवा में अंतराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि 14 फरवरी को आदि बद्री में इस महोत्सव का विधिवत रूप से शुभारंभ होगा और 15 फरवरी को कुरुक्षेत्र विश्विद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गत वर्षो की तरह इस बार के महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। शहर की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा 21 हवन कुंड स्थापित किए जाएंगे। हवन कुंड की तैयारियों के लिए रामधारी शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके लिए प्रशासन द्वारा सम्बंधित विभाग से एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो हवन कुंड की तैयारी में रामधारी शर्मा का सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरती स्थल का चुनाव करते हुए आरती की सम्पूर्ण तैयारियों बारे रामधारी शर्मा को विशेष तौर पर आदेश दिए। एसडीएम ने कहा कि 21 कुंडीय हवन का शुभारंभ प्रात: 10.45 बजे होगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव की गरिमा को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम स्थल से सरस्वती मंदिर तथा संतोषी माता मंदिर के पास से होकर मुख्य स्थान तक के दायरे में परिक्रमा पाथ बनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा परिक्रमा पाथ पर परिक्रमा की जाएगी तथा साथ–साथ 27 नक्षत्रों के पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाने का कार्य 11.30 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चलेगा। एसडीएम ने कहा कि महोत्सव के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों व कार्यक्रम स्थल के आस–पास के क्षेत्रों में लाईटिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर बनाने व महोत्सव की खासियत को दर्शाती पीले रंग की झंडियों की विशेष व्यवस्था करवाई जाए ताकि अंतराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में चार चांद लग सकें। महोत्सव में साऊंड की व्यवस्था सैन्सन पेपर मिल के प्रदीप सैनी द्वारा किया जाएगा। एसडीएम सोनू राम ने कहा कि महोत्सव के दौरान दोपहर एक बजे से 3 बजे तक शब्कोच्चाण किया जाएगा। इसके पश्चात 5.45 पर स्कूल द्वारा सरस्वती वंदना की जाएगी तथा सांय 6 बजे आरती के साथ अंतराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन किया जाएगा।

एलन मस्क की चेतावनी छोड़ना होगा पृथ्वी को

वैज्ञानिकों का मानना है कि सृष्टि के इतिहास में 5 बार 'प्रलय' आ चुकी है जिसमें सबकुछ तबाह हो गया। कुछ शोधों में माना गया है कि पृथ्वी पर प्रलय अक्सर होती रहती है और यह एक चक्र का हिस्सा है। पृथ्वी पर मंडराने वाले इसी खतरे से निपटने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा कई सुरक्षा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यही नहीं मस्क अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जो यह सोचते हैं कि इंसान का भविष्य अंतरिक्ष में है।

मस्क ने कहा, 'साढ़े चार अरब साल के पृथ्वी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन जीने की संभावना है और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर रहा जा सकता है। हालांकि इस अवसर के लिए बहुत कम समय बचा है।'स्पेसएक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने चेताया है कि अगर इंसान ने जल्द से जल्द पृथ्वी को नहीं छोड़ा और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं पर काम नही किया तो मानवता का खत्म होना निश्चित है। स्पेसएक्स कंपनी के मालिक मस्क (49) लंबे समय से यह मांग करते रहे हैं कि इंसानों को दूसरे ग्रहों पर भेजा जाना चाहिए ताकि मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। अमेरिका के अपोलो यान के चंद्रमा पर लैंडिंग के 49 साल बीत चुके हैं और इंसान अभी तक किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर फिर कभी नहीं गया है।

मस्क की योजना है कि अगले 10 साल के अंदर पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह मंगल पर कदम रखा जाए और वहां पर इंसानों को बसाने का काम शुरू किया जाए। आइए जानते हैं कि एलन मस्क ने आगे और क्या–क्या कहा... इंसान के सबसे करीब चंद्रमा और मंगल ग्रह ही हैं। शुक्र और बुध ग्रहों पर जीवन की संभावना नहीं है। मंगल के अलावा बृहस्पति और शनि ग्रह हैं जहां वातावरण गैसों से भरा हुआ है। हालांकि उनके चंद्रमा पर जाया जा सकता है। अरबपति एलन मस्क की इच्छा केवल इन ग्रहों की यात्रा तक सीमित नहीं है। वह इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं और यह सब वह मानवता को बचाने के नाम पर करने का दावा कर रहे हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया ऐप क्लबहाउस पर अपनी कंपनी स्पेसएक्स, टेस्ला और मानवता के भविष्य को लेकर सवालों का जवाब दिया। मस्क ने लोगों को मंगल ग्रह पर खुद से ही खुद को चलाने वाले शहरों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के शहर को बनाकर ही हम इंसानी 'चेतना' को लंबे समय बचा सकते हैं। एलन मस्क ने कहा कि धीरे–धीरे हम इसका सामना कर रहे हैं कि क्या हम एक ऐसे जीव बनेंगे जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह जा सकेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि हम इससे आश्चर्य में आ जाएंगे कि ब्रह्मांड में कई ऐसी खत्म हो चुकी सभ्यताएं होंगी जो करोड़ों साल तक विकास करने के बाद आंतरिक या बाह्य कारणों से धीरे–धीरे खत्म हो गई होंगी। टेस्ला के संस्थापक ने कहा, 'सभी सभ्यताएं एक वृत्त से होकर गुजरती हैं जिसमें उनका विकास होता है, वे तकनीक की जटिलता में आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे चलकर वे बढ़ना बंद कर देते हैं और उनका पतन शुरू हो जाता है। धीरे–धीरे वह सभ्यता खत्म हो जाती है। यह हो चुका है

और अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो जानते होंगे कि भूतकाल में कई सभ्यताएं समाप्त हो गईं थीं। धरती के सबसे अमीर इंसान मस्क ने कहा कि आप मिस्र को देख सकते हैं। करीब 5 हजार साल पहले वहां पर गीजा का एक महान पिरामिड था लेकिन बाद में वहां रह रहे लोग यह भूल गए कि पिरामिड का निर्माण कैसे करना है। इसके बाद वे यह भी भूल गए कि चित्रलिपि को कैसे पढ़ना है।

मस्क ने कहा कि इसी तरह के पाठ को रोमन साम्राज्य, सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता से भी सीखा जा सकता है। मस्क ने कहा, 'इसी बात की पूरी संभावना है कि हम एक वृत्त से होकर गुजरेंगे और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम वापसी के प्रति कम लचीले होंगे। उन्होंने कहा कि धरती को बाहरी खतरे भी हैं। हालांकि उन्होंने इसका ज्यादा विवरण नहीं दिया। बता दें कि आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले डायनासोर धरती पर घूमते थे लेकिन एक 10 किमी लंबे ऐस्टरॉइड के टकराने के बाद वे खत्म हो गए।

किसानों से वादा खिलाफी बजट में साफ दिखी: डॉ बी के कौशक

बोले: मध्यम वर्ग एवं कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया,जबकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी आम आदमी की मदद करने की।

रणदीप रोड़/बातों बातों में

कुरुक्षेत्र। आम आदमी पार्टी के उत्तरी हरियाणा के अध्यक्ष डॉ बी के कौशिक ने आज कुरुक्षेत्र में मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार के बजट को लेकर तीखा हमला किया है।

पार्टी का कहना है कि सरकार ने किसानों को फिर से धोखा दिया है। किसान सरकार से आस लगाए बैठे थे लेकिन अब ठगा महसुस कर रहे है। सरकार ने कृषि बजट 7.8% घटा दिया। लेकिन किसानों के माध्यम से अपनी जेब भरने से नही चुकी और जनता पर कृषि सेस का बोझ जरूर डाला।वही किसान संम्मान निधि में13% तक कि कटोती कर दी।इस बजट में सरकार की मंशा साफ हो गई है कि ये तीनो बिल किसानों की खेती बाड़ी छीन कर उसे सड़क पर लाने की कोशिश है। डॉ कौशक ने बताया कि

सरकार इस बजट में रेल, बैंक, बीमा, रक्षा और स्टील सब कुछ सरकार बेचने जा रही है। यह बजट नहीं ओलेक्स है, जिस पर सरकार ने बजट के रुप में बीमा, रेलवे, डिफेंस, स्अील, बैंक... सब कुछ सेल पर डाल दिया है। पार्टी ने आगे कहा कि ये पूंजीपतियों का बजट है। आज बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप के उत्तरी हरियाणा जोन के सन्गठन मंत्री सुखवीर सिंह ने कहा कि भारत का पहला पेपरलेस बजट 100 फीसदी होपलेस बजट है इसका थीम भारत बेचो है। सुखवीर सिंह ने कहा है कि रेलवे बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचने की तैयारी है, पोर्ट बेचे जा रहे हैं, बीमा सेक्टर बेचा जा रहा है। 23 पीएसयू बेचा जा रहा है। सरकार ने आम आदमी कीपूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि आज जबकि कोरोना के चलते पिछले एक सालसे आर्थिक तंगी का सामना कर रहेआम आदमी खासकर कर्मचारी वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीद थी उसे निराशा ही हाथ लगी है। उसे कर में कोई छूट नहीं मिली है। उल्टे पैट्रोल और डीजल परकृषि सेस और लगा दिया है। उन्होंने कहा कि भले हली आज सरकार यह कह रही है कि इसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा,मगर जल्दी ही इसका उल्टा असर भी देखने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अनदेख कर दिया है।

अमीर अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। आप नेता ने आगे कहा कि इस बजट में नौकरी शुदालोगों के लिए कोई राहत नहीं है। महिला होते हुए भी वित्तमंत्री ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केभाषण में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया। वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट है।

1991 के बाद से यह सबसे बड़ा संकट है।उन्होंने कहा कि बजट में कृषि और किसान की अनदेखी जारी है और उन्होंने कहा कि सरकार ने बेशक अपने इस बजट में एमएसपी डेढ़ गुणा करने की घोषणा कर दी हो,मगर किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जोकि किसानों की इन दिनों सबसे अहम मांग भी है।

मौके पर जोन प्रवक्ता मेवा राम आर्य, जवाहर गोयल, सुरेंद्र मित्तल, बाबूराम मथाना, सुमित हिंदुस्तानी, गौरव बक्शी, जसविंदर राणा , एन पी दहिया और राजेश सैनी आदि मौजूद थे।

पोलियो पिलाओ अभियान में पलवल कॉलेज की छात्राओं का योगदान

कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल कुरुक्षेत्र की एनएसएस इकाई की कार्यक्रम अधिकारी सीमा पांडे के नेतृत्व में महाविद्यालय की 26 स्वयं सेविकाओं ने कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न क्षेत्र जैसे सेक्टर–2,3,4,5, 7,13 तथा तथा शास्त्री नगर, जोशियां मोहल्ला एवं सलारपुर रोड स्थित सरदाना क्लीनिक में सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोलियो पिलाओ अभियान में हिस्सा लिया।

इसके लिए डॉ प्रदीप सिंगला जी के द्वारा उन्हें महाविद्यालय में 23 जनवरी को इस अभियान के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।जिसमें चीफ प्रॉक्टर डॉ मीनाक्षी एवं एनएसएस कमेटी के सदस्य मैडम मोनिका, कोमल गर्ग, पूजा एवं प्रीति ने अपना सहयोग दिया। इस अभियान में छात्राओं ने डॉ प्रदीप सिंगला एवं डॉ सौरव के नेतृत्व मेंउनकी टीम के साथ 31 जनवरी को इन क्षेत्रों में बनाए गए बूथों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने में सहयोग किया एवं 1 और 2 फरवरी को घर घर जाकर बच्चों को दवाई पिलाने का कार्य संपन्न किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य राजेश सैनी के द्वारा छात्राओं के इस प्रयास के लिए उन्हें बधाई दी एवं भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की प्रेरणा दी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक क्लब ने प्रो. आरके देशवाल को दी विदाई पार्टी

कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षक क्लब ने दर्शनशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. आरके देशवाल को उनकी सेवानिवृत्ति पर शिक्षक क्लब में विदाई पार्टी दी। इस मौके पर शिक्षक क्लब के प्रधान डॉ. सोमबीर ने प्रो. आरके देशवाल का स्वागत किया एवं उनके विश्वविद्यालय में कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्रो. आरके देशवाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष, चीफ वार्डन पुरूष, प्रोक्टर एवं अन्य अहम् पदों पर कार्य करते हुए विश्वविद्यालय की बेहतरी के लिए ईमानदारी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य किया है।

प्रो. देशवाल ने विश्वविद्यालय के लिए कठिन परिश्रम और निष्ठा से कार्य किया है। इसके लिए विश्वविद्यालय हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इस अवसर पर प्रो. आरके देशवाल ने अपने मान–सम्मान के लिए शिक्षक क्लब की पूरी टीम तथा समारोह में उपस्थित सभी शिक्षकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में उनकी शैक्षिक यात्रा बहुत सुखद रही। उन्होंने जीवन में खुश रहने के लिए जो मूल मंत्र सीखे, उनके बारे में उन्होंने सभी से अपने विचार सांझा किए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में जिज्ञासु होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण हर व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने जीवन में हर कार्य को सकारात्मकता से हल करने का प्रयास करना चाहिए। संयम, आत्मविश्वास व अनुशासन सफल जीवन का आधार है। इस मौके पर प्रोक्टर प्रो. रमेश भारद्वाज, प्रो. डीएस राणा चीफ वार्डन पुरुष, प्रो. नीलम ढांडा चीफ वार्डन महिला, कुटा प्रधान डॉ. परमेश कुमार, प्रो. अमित लुदरी, प्रो. नीलू सूद, डॉ. सुमन ढांडा, डॉ. गोपाल प्रसाद, डॉ. राजपाल, डॉ. दीपक राय बब्बर, डॉ. महाबीर रंगा, डॉ. कुलदीप, डॉ. मीनाक्षी सुहाग, डॉ. सिम्मी वशिष्ठ, डॉ. रमेश, डॉ. नरेश, डॉ. नफीस अहमद, डॉ. हरविन्द्र सिंह लोंगोवाल, डॉ. ओमप्रकाश ठाकुर, डॉ. जितेन्द्र भारद्वाज, ललित व राम विनय मौजूद रहे।

सामुदायिक विकास को बढ़ाकर ही देश और समाज का विकास सम्भव है: डॉ. बाजपेयी

रणदीप रोड़
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

महाराजा अग्रसैन कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा 'सामुदायिक विकास एवं समाज कल्याण' विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता कॉलेज प्राचार्य डॉ. पी.के.बाजपेयी जी रहे। कार्यक्रम संयोजक डॉ. पवन कुमार त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर के किया। इस अवसर पर अपने प्रेरक उद्बोधन मे डॉ. पी.के.बाजपेयी ने कहा कि 'वर्तमान सरकार की नीतियॉ सामुदायिक विकास एवं समाज कल्याण के चारों और केन्द्रित है क्योकि सामुदायिक विकास को बढ़ाकर ही देश और समाज का विकास सम्भव है। समाज एवं जन कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी नीतियॉ संचालित की जा रही है विद्यार्थी अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार समाज कल्याण की योजनाओं को समझकर सामुदायिक विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। डॉ बाजपेयी ने कहा कि सामुदायिक विकास करने के लिए आवश्यक है कि गाँव का विकास गाँव के लोागो पर छोड़ दिया जाए, लोगो को ऐसे समान अवसर उपलब्ध कराये जाऐं जिनसे उनका विकास हो सके। कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधन, नये बीज,खाद आदि की व्यवस्था के साथ–साथ किसान सहकारी समितियों का गठन किया गया है जिनमें अभी सुधार की आवश्यकता है। कार्यक्रम की विशिष्ट वक्ता एवं अर्थशास्त्र विभाग की प्रो. पूनम गर्ग ने समाज कल्याण एवं समुदाय के विकास में आर्थिक गतिविधियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू

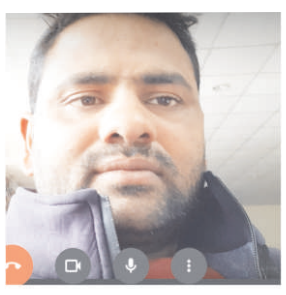

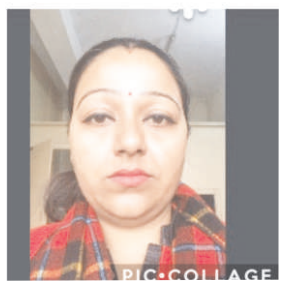

उत्पाद किसी भी देश के जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था के विकास का मानक माना जाता है, एक निश्चित समय में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त माल और सेवाओं का बाजार मुल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। यह आर्थिक दृष्टिकोण से देश के विकास को मापता है। समाज कल्याण एवं सामुदायिक विकास के लिए आवश्यक है कि लोग आर्थिक रूप से सुद्रढ़ बने, इसके लिए सरकार और समाज के जिम्मेदार लोग ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाहन करें। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक एवं विभाग के अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 'स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को प्रगति के मार्ग पर गतिशील करने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय को विकसित करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरूवात 55 विकासखण्डों की स्थापना करके की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, समाज कल्याण आजीविका, समृद्धि और सामाजिक जागरूकता के समान अवसर सृजित करना था ताकि अधिक से अधिक लोग आत्मनिर्भर बन सके। वर्तमान समय में समाज कल्याण से सम्बंधित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण जीवन आदि क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे है। विद्यार्थी भी समाज एवं देश के विकास एवं समाज कल्याण में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए आगे आयें। कार्यक्रम के इस इवसर पर प्रो. सीमा जैन ने विद्यार्थियों को अपने प्रेरक विचारों से लाभान्वित कर व्याख्यान में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इस अवसर पर डॉ. बहादुर सिंह, डॉ. विरेन्द्र सिंह ढ़िल्लों, प्रो. अशोक अग्रवाल आदि अध्यापक उपस्थित रहे।

स्वच्छता सर्वेक्षण में अब सामुदायिक शौचालयों के बाहर अंकित किए गए क्यूआर कोड से दे सकेंगे फीडबैक :सुधा

रणदीप रोड़
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

अब तक 27 हजार 229 लोग दे चुके है फीडबैक, 31 मार्च तक सिटीजन फीडबैक लिंक रहेगा एक्टिव, फीडबैक में थानेसर नगर परिषद प्रदेश में है दसवें स्थान पर

विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लोगों की फीडबैक बहुत जरुरी है। इस शहर के लोगों से फीडबैक लेने के लिए नगर परिषद के सभी सार्वजनिक शौचालयों के बाहर क्यूआर कोड अंकित कर दिया गया है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से शहर के सिटीजन अपनी फीडबैक दे सकते है। अहम पहलू यह है कि थानेसर नगर परिषद सिटीजन फीडबैक की रिपोर्ट में दसवें स्थान पर है।

विधायक सुभाष सुधा बुधवार को देर सायं सैक्टर 7 आवास कार्यालय पर स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा और नप अध्यक्षा उमा सुधा ने नगर परिषद के अधिकारियों से थानेसर नगर परिषद के स्वच्छता सर्वेक्षण से सम्बन्धित फीडबैक रिपोर्ट हासिल की है। विधायक ने कहा कि नगर परिषद थानेसर के सिटीजन से फीडबैक लेने का आनलाईन लिंक 31 मार्च तक एक्टिव रहेगा और इस लिंक पर अब तक 27 हजार 229 लोग अपनी फीडबैक दे चुके है। थानेसर नगर परिषद फीडबैक देने में नगर निगमों को भी पीछे छोड़ चुका है। यह नगर परिषद सिटीजन फीडबैक की रिपोर्ट में हरियाणा प्रदेश में दसवें स्थान पर है।उन्होंने लोगों से अपील की है कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अधिक से अधिक लोग अपनी फीडबैक दे ताकि सिटीजन फीडबैक के लिए थानेसर नगर परिषद प्रदेश में अव्वल स्थान पर पहुंचे। इस सिटीजन फीडबैक में अधिक से अधिक लोगों को जोडने के लिए थानेसर नगर परिषद के 18 सामुदायिक शौचालय, एक कर्मीशियल शौचालय और 4 ई–शौचालयों के बाहर क्यूआर कोड व बार कोड अंकित कर दिया गया है। इन शौचालयों के बार कोड से आम नागरिक सिटीजन फीडबैक पर अपनी रिपोर्ट दे सकता है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए की शहर के सभी वार्डों में स्वच्छता पर विशेष फोकस रखा जाए और नियमित रुप से शहर की मुख्य सडकों, वार्डों की गलियों और नालियों को साफ किया जाए तथासीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। इसके साथ ही डम्पिंग स्थलों पर रोजाना सफाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा घर–घर से नियमित रुप से कचरा एकत्रित किया जाए। इस मौके पर नप अध्यक्षा उमा सुधा, पार्षद मुकुंद सुधा, भाजपा युवा नेता साहिल सुधा, समाज सेवी प्रदीप झाम्ब सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

थानेसर शहर को सबसे स्वच्छ और स्मार्ट नगरी के रुप में किया जा रहा है विकसित :उमा

रणदीप रोड़
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

नप अध्यक्षा उमा सुधा ने वार्ड 15 और वार्ड 23 में 20 लाख की गलियों के निर्माण कार्य का किया शुभारम्भ, हर वार्ड में किए जा रहे है विकास कार्य

नगर परिषद की अध्यक्षा उमा सुधा ने कहा कि थानेसर शहर को सबसे स्वच्छ और स्मार्ट नगरी के रुप में विकसित किया जा रहा है। इस लिए हर वार्ड में तेजी के साथ विकास कार्य किए जा रहे है और स्वच्छता पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है।

इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विशेष अनुदान राशि भी मुहैया करवाई जा रही है। नप अध्यक्षा उमा सुधा बुधवार को वार्ड 15 हरी नगर और वार्ड 23 एकता विहार में सडकों के निर्माण कार्य को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इससे पहले नप अध्यक्षा उमा सुधा, पार्षद विशाल शर्मा, पार्षद भारत भूषण सिंगला ने वार्ड 15 हरी नगर और वार्ड 23 एकता विहार में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 2 गलियों के निर्माण कार्य का विधिवत रुप से शुभारम्भ किया। नप अध्यक्षा ने कहा कि शहर के सभी 31 वार्डों में विकास कार्य करवाएं गए है और अब भी लगातार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। सभी वार्डों में समान रुप से बिना भेदभाव के विकास कार्य किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही थानेसर शहर में ऐलिवेटिड रेल ट्रैक का निर्माण कार्य शुरु हो जाएगा। इस प्रोजैक्ट पर जहां सरकार द्वारा 225 करोड़ रुए की राशि खर्च की जाएंगी। वहीं शहर वासियों को 5 फाटकों से भी निजात मिलेगी। इससे शहर का सौंदर्यकरण भी होगा और रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल पाएगी और पर्यावरण में भी सुधार होगा।

इसी तरह सरकार द्वारा शहर को विकसित करने पर कई परियोजनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। इस मौके पर नैब सिंह, संजय, सतीश शर्मा, रणबीर, राजेन्द्र, अभिषेक, ओमप्रकाश, राजीव गर्ग, शशि, धर्म सिंह राणा, विलायती राम अरोड़ा, मोहन बजाज, कृष्ण कुकरेजा, संजीव बंसल, यशपाल, जगदीश आदि मौजूद थे।

अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

जिला पुलिस कुरूक्षेत्र ने अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में किया एक को गिरफ्तार।

थाना लाडवा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बलकार सिहं की टीम ने गुप्त सुचना के आधार पर रामकरण पुत्र रामकिशन वासी दुधला को ब्राहण मोड लाडवा पर अवैध रुप से शराब बेचते हुए काबु करके उसके कब्जा से 9 बोतल शराब देशी बरामद की। आरोपी के खिलाफ थाना लाडवा में आभकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसको बाद में पुलिस बेल पर रिहा किया गया ।

सडकों पर अपने वाहन अवैध पार्क करने तथा यातायात नियमों का अवहेलना करने वाले सावधान

कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

जिला कुरुक्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा यातायात को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से चलाने के मकसद से पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र, श्री हिमांशु गर्ग ने जिला कुरुक्षेत्र को ट्रैफिक के तीन जोनों में बांट कर, सभी तीन जोनों में निरीक्षक स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है।

जिला कुरुक्षेत्र की ट्रैफिक को ठीक प्रकार से चलाने के लिए 25 चिता राईडर्रों को नियुक्त किया गया है। जो दो शिफ्टों में दिन रात आप की सेवा के लिए सड़कों पर हाजिर रहती है। शहर तथा उसके आसपास यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए जन सहयोग की आवश्कता है। पुरे देश में सड़क दुर्घनाओं में कमी लाने के लिए 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस माह के दौरान पुलिस भिन्न भिन्न तरीकों से लोगों को जागरूक करने के साथ–साथ कानुन का भी सहारा लिया जा रहा है। प्राय: देखने में आया है कि लोग अपने वाहनों को बिना सोचे समझे सडकों के बाच में खडा कर देते हैं जिससे सडक पर गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को कठिनाई का सामना करना पडता है जिससे सडक दुर्घटनाओं की सम्भावना और अधिक बढ जाती हैं। जिसको कम करने के लिए वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों के तहत कार्यावाही की जा रही है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के उद्धेश्य से उप पुलिस अधीक्षक श्री राजकुमार की देख–रेख में निरीक्षक देवेन्द्र कुमार, रामकरण तथा निरीक्षक रमेश कुमार को अलग–अलग जोनों के प्रभारी नियुक्त किया गया है । पुलिस अधीक्षक कुरूक्षेत्र, श्री हिमांशु गर्ग ने स्वयं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों तथा सडकों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कानुनी कार्यावाही करने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिए । सभी जोन प्रभारी यातायात के दवारा यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सडकों पर अवैध रुप से वाहन पार्क करने तथा यातायात नियमों का अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कानुनी कार्यावाही भी की जा रही है ।

डॉ. अशोक शर्मा बने फैकल्टी डेवलपमेंट सेन्टर के द्वितीय कार्यक्रम संयोजक

रणदीप रोड़
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान के सहायक प्रोफेसर डॉ. अशोक शर्मा को विश्वविद्यालय के फैकल्टी डेवलपमेंट सेन्टर का द्वितीय कार्यक्रम संयोजक बनाया गया है। लोकसम्पर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. दीपक राय बब्बर ने बताया कि एफडीसी सेन्टर में आईआईटीआर की प्राचार्या डॉ. तरूणा ढल कार्यक्रम संयोजिका के रूप में काम कर रही है। वहीं अब डॉ. अशोक शर्मा को द्वितीय कार्यक्रम संयोजक का कार्यभार सौंपा गया है।

राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी 6 फरवरी तक प्राप्त कर सकते है राशन

कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक ने मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माह जनवरी 2021 के राशन का वितरण आगामी 6 फरवरी 2021 (शनिवार) तक कर दिया जाएगा, जो लाभार्थी माह जनवरी में राशन प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, वह अब आगामी 6 फरवरी, 2021 तक सम्बन्धित राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकते है।

उन्होंने कहा कि राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्याधशिकायत होने पर सम्बन्धित उपायुक्त, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अथवा खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मुख्यालय की हैल्पलाईन नंबर 1967 (बीएसएनएल) एवं 1800–180–2087 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है।

प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पर हर भारतीय को गर्व : बवेजा

रणदीप रोड़
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

ग्लोबल इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के चेयरमैन, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े एडवोकेट मधु सूदन बवेजा ने कहाकि अंतरिक्ष में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम लिखने वाली प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पर हर भारतीय को गर्व है और उन की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

उन्होंने कहाकि यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो असंभव को संभव किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है। यह सब कर दिखाया है भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री स्व. कल्पना चावला ने। बवेजा ने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि पर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज किसी भी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कम नहीं है। जिसकी प्रेरणा हमें कल्पना चावला तथा अन्य भारतीय दृढ़ संकल्प महिलाओं से ही मिली है। वह ऐसी कर्मठ तथा प्रतिभा की धनी महान वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष यात्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं।

देश की 109 नराकासों में प्राप्त हुआ समिति को यह सम्मान

एनडीआरआई की अध्यक्षता में नराकास को मिली है यह उपलब्धि

रणदीप रोड़
करनाल/बातों बातों में

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के अध्यक्षीय समन्वय में करनाल में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा उत्तर क्षेत्र–प्रथम के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार 2019–20 में द्वितीय स्थान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को यह सम्मान हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित 109 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में राजभाषा हिन्दी के प्रचार, प्रसार व कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय प्रयासों के मूल्यांकन में प्रदान किया गया है।

समिति के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा. मनमोहन सिंह चौहान ने इस सम्मान के लिए समिति के सभी सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों, समिति के निवर्तमान अध्यक्ष डा. आर.आर.बी. सिंह, नराकास समन्वयक श्री विवेक पुरवार संयुक्त निदेशक(प्रशासन) व कुलसचिव, श्री डी.डी. वर्मा, नियंत्रक, समिति के सदस्य सचिव श्री राकेश कुमार कुशवाहा, नराकास वित्तीय समन्वयक श्री कुणाल कालड़ा, नराकास संयोजक श्री धीरज शर्मा, सभी राजभाषा अधिकारियोंव समन्वयकों को शुभकामनाएं संप्रेषित की हैं। डा. मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार के करनाल में स्थित कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एक संयुक्त मंच प्रदान करती है, जहां सदस्य कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान हर साल जून व नवंबर माह में दो बैठकों में राजभाषा के कार्यान्वयन की समीक्षा कर निर्णित बिन्दुओं पर कार्रवाई करते हैं।

नराकास करनाल राजभाषा विभाग, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति समय–समय पर सदस्य कार्यालयों में राजभाषा नीति, नियमों व व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कर मार्गदर्शन प्रदान करती है। डा. चौहान ने यह भी बताया कि न.रा.का.स. करनाल की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी।

समिति के द्वारा समय समय पर विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं, हिन्दी पखवाड़ा कार्यक्रमों, हिन्दी कार्यशालाओं, वैज्ञानिक संगोष्ठियों, वार्ता कार्यक्रमों, कवि सम्मेलनों व अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन भी किया जाता है। समिति के द्वारा वर्ष 1994–95 से गृह पत्रिका ''कर्णोदय'' भी प्रकाशित की जा रही है। इस पत्रिका के छमाही अंकों में नराकास करनाल के समिति व सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न राजभाषा गतिविधियों तथा सदस्य कार्यालयों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को हिन्दी आलेखों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है।

भारत सरकार के द्वारा पूर्व में समिति को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2005–2006 तथा 2007–2008 में 'इंदिरा गाँधी राजभाषा चल वैजयन्ती'' का सम्मान भी प्रदान किया जा चुका है।

डा. चौहान ने समिति की गतिविधियों को समय समय पर व्यापक रूप से जन–जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों व दृश्य–श्रव्य मीडिया के बहुमूल्य योगदान के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

कुवि के यूजीसी मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यशाला सम्पन्न

पुष्पा रानी
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूजीसी मानव संसाधन विकास केन्द्र द्वारा आयोजित साप्ताहिक मूक एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रम कार्यशाला का 2 फरवरी को समापन हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूजीसी मानव संसाधन विकास केन्द्र की निदेशिका प्रो. नीरा वर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की योजना, विकास एवं प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिनन मुद्दों का समाधान करना था। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं संस्थानों के 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में जीव विज्ञान, सांख्यिकी, कम्प्यूटर, वाणिज्य, विधि, विज्ञान एवं लाइब्रेरी से सम्बन्धित पृष्ठभूमि के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. सुनीता दलाल ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रीजनल सेन्टर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के प्रो. विनोद गर्ग ने प्रतिभागियों को कोरोना महामारी के समय में ऐसी कार्यशालाओं के महत्व के बारे में प्रेरित किया। उन्होंने मूक, स्वयम और ई–पाठशाला के लिए नए पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डीन रिसर्च एंड

डेवलपमेंट, डीन ऑफ कॉलेज प्रो. अनिल वोहरा ने वर्तमान परिदृश्य में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षण के पारम्परिक तरीकों के साथ मिश्रित करने के लिए नए शिक्षण संसाधनों के महत्व पर जोर दिया। साप्ताहिक कार्यशाला में बतौर रिसोर्स पर्सन डॉ. दीपक बिस्ला, प्रो. अनुरेखा शर्मा, अनुराग सांगवान, डॉ. माधुरी हुड्डा, डॉ. तेजिन्द्रपाल सिंह, डॉ. निशा, डॉ. नवजोत कौर, डॉ. मनप्रीत सिंह व डॉ. तरूणा ढल ने अपने विचार सांझा किए।

कार्यशाला में आफलाइन साफ्टवेयर, क्लाउड आधारित साफ्टवेयर व मोबाईल एप्लिकेशन के माध्यम से ई–सामग्री बनाने के बारे में बताया गया। कार्यशाला में डॉ. अमित व डॉ. सुरेन्द्र ने कंप्यूटर विषय से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी बारीकियों में बताया। इस कार्यशाला के समापन सत्र में विश्वविद्यालय की डीन अकेडमिक अफेयर्स प्रो. मंजूला चौधरी ने अपने सम्बोधन में सीखने के विभिन्न प्रतिमानों को बनाए रखने के विषय में बताया।

कुवि के शिक्षक क्लब मे काव्यांजलि कार्यक्रम आज

कुरुक्षेत्र, 4 फरवरी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का शिक्षक क्लब शुक्रवार को काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन करेगा। कुवि शिक्षक क्लब के प्रधान डॉ. सोमबीर ने बताया कि 5 फरवरी को सांय 5 बजे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक क्लब में होने वाले काव्यांजलि कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा मुख्यातिथि होंगे। कुवि शिक्षक क्लब के सचिव डॉ. चन्द्रकांत ने बताया कि इस कवि सम्मेलन समारोह में मशहूर कवि डॉ. केके ऋषि, डॉ. बलवान सिंह, सूबे सिंह सुजान, प्रकाश, डॉ. संजीव अंजुम, शमीम हयात, दिव्या कोचर, दीपक मासूम, डॉ. सलोनी पी दीवान व डॉ. बृजेश कठिल कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

कुवि के 28 विद्यार्थी आईसीआईसीआई बैंक में चयनित,कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने दी बधाई

पुष्पा रानी
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 28 विद्यार्थियों का कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक में चयन हुआ है। इस अवसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट आफिसर डॉ. महेन्द्र सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी प्लेसमेंट सैल के द्वारा कैम्पस प्लेसमेंट कार्यक्रम के तहत आई सी आई सी आई बैंक को एमबीए के विद्यार्थियों की प्लेसमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पन्न हुई। इसमें एमबीए दो वर्षीय व पंचवर्षीय कोर्स के विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवदेन किया और सभी का साईकोमीट्रिक टेस्ट हुआ। इसके बाद 22 जनवरी को बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया।

इस पूरी चयन प्रक्रिया का समन्वय विश्वविद्यालय की प्लेसमेंट सैल द्वारा आयोजित किया गया जिसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चयन प्रक्रिया के बाद बैंक की ओर से जारी सूची में 18 छात्र–छात्राएं चयनित हुए। चयनित विद्यार्थियों में दिशा मदान, नितिन कुमार, सचिन गौर, सूरज हुड्डा, आशू, हेमन्त मोंगा, तुषार गांधी, साक्षी,

पलक मनोचा, रोहित वर्मा, गुंजन, जतिन जुनेजा, प्रभजोत सिंह, रोहन सिंह, अंकिता, चिराग मेहता, यशस्वी व अंजलि शामिल हैं।डॉ. महेन्द्र सिंह ने बताया कि इन 18 विद्यार्थियों के अतिरिक्त 10 विद्यार्थियों का चयन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा पहले ही कर लिया गया था व इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सैल को सूचित कर दिया गया था। इन चयनित विद्यार्थियों में अनमोल सिंह, विशाल, हर्षित, सुभांगी, रणजीत, शुभम कुमार, तेजेन्द्र सिंह, यशुदेव, स्मृति व नीरज गुलाटी शामिल हैं। सभी 28 चयनित विद्यार्थी आईसीआईसीआई बैंक में उप–प्रबन्धक पद पर कार्यरत है। इन्हें 4.12 लाख रुपए का सैलेरी पैकेज दिया गया है।

अपनी अंतिम परीक्षा के बाद चयनित विद्यार्थी जून–जुलाई 2021 में बैंक में ज्वाईन करेंगे। इस पूरी चयन प्रक्रिया में डॉ. सिम्मी अरोड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अनमोल और रोहन सिंह ने विद्यार्थियों के ऑनलाइन साक्षात्कार सम्पन्न करने में समन्वयक कार्य बखूबी सम्भाला। विभाग के सभी शिक्षकों ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी है।

अधिकारियों को आनलाईन फाईल मूव करने के दिए आदेश

पुष्पा रानी
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी कार्यालयों में कागज रहित कार्य करने के लिए ई–आफिस प्रणाली को अमलीजामा पहनाया गया है। इसलिए सभी अधिकारी अपने कार्यालयों की फाईलों को ई–आफिस के माध्यम से ही भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने जारी आदेशों में कहा है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी कार्यालयों में कागज रहित कार्य करने के लिए सभी प्रकार की फाईलों को मैन्यूअल ना भेज कर आनलाईन के माध्यम से निकालने के लिए ई–आफिस को चलाया गया है। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी अपने कार्यालय की फाईल ई–आफिस के माध्यम से ही भिजवाना सुनिश्चित करे। अब मैन्यूअल फाईले भेजने की कार्यप्रणाली के बदले। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में कोई भी मैन्यूअल ना भिजवाकर आनलाईन ई–आफिस के माध्यम से ही उपायुक्त कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

भारत के लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में अपार संभावनाएं : प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा

कुवि के रूसा प्रोजेक्ट के तहत स्थापित उद्यमिता केंद्र द्वारा विद्यार्थियों के लिए 10 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ

संवाददाता
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि भारत को विश्व के पटल पर एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभारने के लिए भारत के लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यह केवल तभी संभव है जब हमारे आज के विद्यार्थी कल के सफल उद्यमी बन पाएं।

वे गुरूवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रूसा प्रोजेक्ट के तहत् स्थापित उद्यमिता केंद्र द्वारा विद्यार्थियों के लिए 10 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर कुलपति प्रो. सोमनाथ ने विद्यार्थियों को इस कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन इत्यादि का लाभ उठाकर रोजगार सृजक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि छोटे लघु एवं मध्यम उद्योगों का ना केवल आर्थिक बल्कि देश के सामाजिक विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसे महिलाओं की भागीदारी से और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने विशेष रुप से छात्राओं का उद्यमी बनने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की डीन अकेडमिक अफेयर्स व रूसा की नोडल अधिकारी प्रोफेसर मंजूला चौधरी ने भारत में रोजगार के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों में कौशल निर्माण एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की कार्यशाला के आयोजन पर बल दिया। रूसा के तहत् स्थापित उद्यमिता केंद्र के कोर्डिनेटर प्रोफेसर राजेंद्र नाथ ने केंद्र के द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशाला की श्रृंखला में आयोजित इस छठी कार्यशाला पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया की कार्यशाला के लिए आए आवेदनों में से केवल 60 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ. योगेश वर्मा ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सफल उद्यमी बनने के कुछ सूत्र बताए। कार्यशाला की संयोजिका डॉ रंजना ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया। कार्यशाला में मंच संचालन आयोजन सचिव डॉ. अर्चना चौधरी ने किया। इस अवसर पर उद्यमिता केंद्र के सदस्य प्रोफेसर राकेश कुमार, प्रोफेसर सुदेश, डॉ. सिमी वशिष्ठ, डॉ. विकास अग्रवाल एवं डॉ. कंवल गर्ग भी उपस्थित रहे। इस प्रकार की कार्यशालाओं के द्वारा विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी प्रदान करने वाला बनाने के लिए प्रयासरत है। आयोजित इस छठी कार्यशाला पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया की कार्यशाला के लिए आए आवेदनों में से केवल 60 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ. योगेश वर्मा ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सफल उद्यमी बनने के कुछ सूत्र बताए। कार्यशाला की संयोजिका डॉ रंजना ने धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया। कार्यशाला में मंच संचालन आयोजन सचिव डॉ. अर्चना चौधरी ने किया।

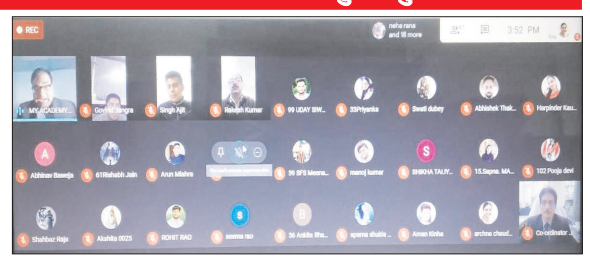

Contact No. : +91-99913-12577, +91-87081-27462

सिंदूरी
BY SUMIT GARG

DESIGNER BOUTIQUE

We Deal In Bridal Lehanga Choli,
Suits, Kurtis, Dupatta &
Embroidery Work On Order .

Contact For Franchise To Open सिंदूरी BY SUMIT GARG Store.

First Floor, Opp. Saini Public School, Chanarthal Road, Kurukshetra

कुरुक्षेत्र साई में कोविड के बाद अब शुरु होंगी गाईडलाईंस के अनुसार खेलकूद गतिविधियां: गुरविन्द्र

कोविड गाईडलाईंस के अनुसार प्रथम चरण में 12 खिलाडियों के साथ शुरु हुआ साई हास्टल, 3 चरणों में शुरु होगा हास्टल

रणदीप रोड़
कुरुक्षेत्र/बातों बातों में

कोविड–19 के कारण करीब 1 साल के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण कुरुक्षेत्र शाखा को शुरु किया गया है। इस साई हास्टल को कोविड गाईडलाईंस और विभाग की एसओपी के अनुसार प्रथम चरण में 12 खिलाडियों के साथ शुरु किया गया है, जिसमें 8 हॉकी के खिलाड़ी और 4 वॉलीबाल के खिलाड़ी शामिल है।

साई प्रभारी गुरविन्द्र सिंह ने वीरवार को बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण की क्षेत्रिय निदेशक ललिता शर्मा के आदेशानुसार कोविड–19 की गाईडलाईंस की पालना करते हुए कुरुक्षेत्र के साई सेंटर को प्रथम चरण में शुरु किया गया है। इस प्रथम चरण में 12 खिलाडियों को रखा गया है। इसके उपरांत द्वितीय और तृतीय चरण में एसओपी के अनुसार पूर्णत: शुरु कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही हॉस्टल की मुरम्मत और रंग रोगन

करवाया गया है। अभी हाल में ही 9 कमरे पूर्णत: तैयार हो गए है और एक कमरे में दो खिलाडियों को रहने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र साई सेंटर के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक मुकाम हासिल कर चुके है। इस सेंटर से प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले हॉकी खिलाड़ी सुरेन्द्र कुमार पालड़ भारतीय हॉकी टीम के सदस्य है। इसके अलावा साईक्लिंग और वॉलीबाल के खिलाड़ी भी अंतराष्ट्रीय स्तर पर कुरुक्षेत्र व हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर चुके है। उन्होंने कहा कि खिलाडियों को प्रशिक्षण देने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इन खिलाडियों को रहने, खाने, किट और प्रशिक्षण की नि:शुल्क सुविधाए दी जा रही है। इस मौके पर सतपाल सिंह, कुलदीप सिंह वडैच, अनीता शर्मा, सुदेश शर्मा, राहुल सांगवान, सुधीर दहिया, जनिता कटारिया, जगदीप सिंह आदि उपस्थित थे।

डा.शेर को कांग्रेस में शामिल कराने के सूत्रधार बने हैं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा

बातों बातों में

चंडीगढ़: जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) एससी सैल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.जीत सिंह शेर भी अब पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे। डा.शेर के वीरवार शाम को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की संभावना है। इसकी पुष्टि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने की है। डा. जीत सिंह शेर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सुप्रीडेंट के पद पर कार्यरत हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ (कुंटिया) के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले दो दिनों के अंतराल में पड़ौसी जिला करनाल के जेजेपी जिलाध्यक्ष एवं आईटी विंग के पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा दिये जाने के बाद कुरुक्षेत्र जिला वासी जेजेपी एससी सैल के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष का इस्तीफा देने से जननायक जनता पार्टी को बड़े झटकों से कम नहीं। इन सभी इस्तीफों के पीछे किसान आंदोलन का समर्थन और तीन कृषि कानूनों का विरोध माना जा रहा है। काबिलेजिक्र है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ ने बताया है कि डा.शेर को कांग्रेस में शामिल कराने के सूत्रधार पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा बने हैं।

स्वामी मुद्रक प्रकाशक एवं संपादक पुष्पा रानी द्वारा ओजोन प्रिंटर्स, प्लाट नंबर 13, ज्योति नगर कुरुक्षेत्र 136 118 हरियाणा से छपवाकर बातों बातों में कार्यालय 902 ऐ गुरुदेव नगर के डी बी रोड कुरुक्षेत्र हरियाणा से प्रकाशित किया संपादकीय कार्यालय बातों बातों में 902 ऐ गुरुदेव नगर के डी बी रोड कुरुक्षेत्र हरियाणा 136118 मो.नंबर 98120-08227 संपादक पुष्पा रानी